vishikhamedia@gmail.com
विभिन्न विषयों पर आधारित राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
RNI No. RAJHIN/2019/77486

_vishikhamedia/ vishikhamedia/

तीर निशाने पर

विशिखा

मूल्यः 25 रूपये
vishikhamedia vishikhamedia.in
वर्ष:07 अंक:8 अगस्त 2025 पृष्ठ:32

राजस्थान संस्करण

कहां रुकेंगे अखिलेश

ब्राह्मण-ठाकुर के बाद अब साधु-संतों का अपमान

अखिलेश जब भी मुंह खोलते हैं उनके मुंह से सनातन के खिलाफ जहर ही निकलता है। कभी वह ब्राहमणों को कोसते हैं तो कभी ठाकुरों के लिये अपमानजनक भाषा बोलते हैं।

विशिखा

विशिखा न्यूज़ 24x7

आपकी बात, आपके साथ

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

विशिखा

अब डिजिटल एडिशन में भी उपलब्ध

www.vishikhamedia.in

अंदर

12

तेल पर चलेगा अमेरिका का डंडा या भारत की कूटनीति?

08 अखिलेश को बड़ा झटका देने की तैयारी में ब्राह्मण समाज

10 बाजार दिखा बड़ा लेकिन खरीदार है छोटा क्या टिक पाएगी टेस्ला इंडिया में?

16 योगी की सख्ती से यूपी छोड़ रहे हैं दिग्गज ब्यूरोक्रेट्स

18 शिक्षकः ज्ञान के वाहक या वैचारिक प्रचारक

20 कट्टरपंथ के खिलाफ पढ़े-लिखे मुसलमानों की खामोशी के मायने

22 साथ आये उद्धव-राज ठाकरे की मराठी मानुषों पर सियासी नजर

24 बिहार में वोटर लिस्ट जांच पर सबके अपने दावे और विचार

26 मोहर्रम के दौरान ईरानी नेता खामनेई के कसीदे क्यों

28 बिहार चुनाव 2025
ईमान, इस्लाम और इंतकाम के त्रिकोण में उलझा मुस्लिम वोट बैंक

30 राजस्थान में बेटी के जन्म पर मिलेगी १.५० लाख की सहायता

विशिखा
तीर निशाने पर
अंक: 8 वर्ष:07, अगस्त 2025

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
प्रियल श्रीवास्तव
सम्पादक
अनिल कुमार श्रीवास्तव
डिजाइन
देवेन्द्र नेगी, उत्तराखण्ड

विशिखा
तीर निशाने पर

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक **अनिल कुमार श्रीवास्तव** द्वारा **भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, डी.बी. कॉर्प लिमिटेड** शिवदासपुरा, टोंक रोड़, जयपुर से छपवाकर एवं **विशिखा मीडिया** 191/56 (जानकी देवी स्कूल के पास) सेक्टर-19, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर- 302033 राजस्थान के लिए प्रकाशित

पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका मे प्रकाशित सामग्री के विषय मे अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव अवश्य भेजें। अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझावों को आप हमें vishikhamedia@gmail.com पर ई-मेल भी कर सकते हैं।
लेखकों से निवेदन है कि कृपया अपनी स्व-लिखित एवं मौलिक रचनायें ही भेजें। रचनाओं के साथ अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल एवं फोटो अवश्य भेजें। रचनाओं के छापने या न छापने का अधिकार संपादकीय मंडल का होगा। अस्वीकृत रचनायें लौटाई नहीं जाएंगी।
पत्रिका मे प्रकाशित सभी लेख एवं रचनाओं में संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है। पत्रिका मे प्रकाशित आलेख एवं रचनायें लेखकों के निजी विचार हैं। प्रकाशित सामग्री के उपयोग करने से पूर्व में संपादक की लिखित सहमति आवश्यक है।
*किसी भी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) होगा।
*पत्रिका मे प्रकाशित कुछ चित्र, लेख एवं आंकड़ो को इन्टरनेट एवं अन्य वेवसाइट से लिया गया है।

विशिखा न्यूज़ 24x7
आपकी बात, आपके साथ

सम्पादक की कलम से

अनिल कुमार श्रीवास्तव

बरेली में एक शिक्षक के द्वारा पढ़ी गई कविता ष तुम कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलानाष पर मचा बवाल सिर्फ एक कविता पर विवाद नहीं है, बल्कि यह भारत में धार्मिक आस्था, शिक्षा, तर्क और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच खिंची उस लकीर का उदाहरण है जो आज की तारीख में लगातार गहरी होती जा रही है। कविता का यदि मूल भाव देखा जाए, तो छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना था।

भारत जैसे देश में, जहां धर्म केवल आस्था का नहीं, बल्कि जीवन पद्धति का हिस्सा है, वहां किसी धार्मिक परंपरा को इस प्रकार नकारात्मक रूप में दिखाना केवल विवाद नहीं, बल्कि सामाजिक विभाजन को दो ध्रुवों में बाँटना है, एक ओर वे लोग हैं जो तर्क, वैज्ञानिक सोच और शिक्षा को सर्वोपरि मानते हैं और दूसरी ओर वे हैं जो परंपरा, आस्था और धार्मिकता को अपनी पहचान का मूल मानते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ये दोनों विचारधाराएं एक-दूसरे की विरोधी हों? समाज ऐसा बनाना चाहिये, जहां एक बच्चा शिवभक्त भी हो और वैज्ञानिक सोच वाला भी? जो बच्चा कांवड़ भी उठा सकता है, वही बच्चा वैज्ञानिक भी बन सकता है? भारत देश में धर्म और ज्ञान साथ चलते हैं। हालांकि शिक्षक ने माफीनामा जारी कर कहा कि उनका उद्देश्य किसी धर्म का अपमान करना नहीं था। उधर दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षक के समर्थन में बयान देते हुए कहा जो शिक्षक बच्चों को ज्ञान की बात कर रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर करना गलत है। देखा जाय तो यह विवाद एक आईना है, जिसमें भारत की शिक्षा व्यवस्था, धार्मिक और राजनीतिक हस्तक्षेप साफ-साफ देखा जा सकता है। शिक्षक अब पढ़ाने वाले न होकर विचारधारा का माध्यम भी बनते जा रहे हैं। जो कि एक खतरनाक स्थिति है।

शेष फिर....

यूट्यूब के बाद अब फेसबुक भी दूसरों का कंटेंट शेयर करने वालों के खिलाफ करेगा कार्रवाई

मेटा ने बताया कि इस साल हटाए गए करीब १ करोड़ फेक अकाउंट ऐसे थे जो खुद को बड़े क्रिएटर्स की तरह दिखा रहे थे। साथ ही, उसने करीब ५ लाख अकाउंट्स पर स्पैम और झूठी गतिविधियों के लिए पाबंदियां लगाई हैं, जैसे कमेंट्स की अहमियत घटाना या पोस्ट्स की रीच सीमित करना।

यूट्यूब के बाद अब मेटा ने भी फेसबुक पर उन अकाउंट्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने की घोषणा की है, जो बार–बार दूसरों का कंटेंट शेयर करते हैं। कंपनी ने कहा कि जो प्रोफाइल लगातार किसी और के टेक्स्ट, फोटो या वीडियो को कॉपी कर पोस्ट करती हैं, उन पर अब कड़ी कार्रवाई होगी।

मेटा ने बताया कि इस साल हटाए गए करीब 1 करोड़ फेक अकाउंट ऐसे थे जो खुद को बड़े क्रिएटर्स की तरह दिखा रहे थे। साथ ही, उसने करीब 5 लाख अकाउंट्स पर स्पैम और झूठी गतिविधियों के लिए पाबंदियां लगाई हैं, जैसे कमेंट्स की अहमियत घटाना या पोस्ट्स की रीच सीमित करना। कंपनी ने साफ किया कि वे उन यूजर्स को निशाना नहीं बनाएंगे, जो किसी कंटेंट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, ट्रेंड में भाग लेते हैं या अपनी राय जोड़कर पोस्ट करते हैं। असली कार्रवाई उन अकाउंट्स पर होगी, जो जानबूझकर दूसरे का कंटेंट हूबहू कॉपी कर शेयर कर रहे हैं, चाहे वे स्पैम प्रोफाइल हों या नकली क्रिएटर। ऐसे अकाउंट्स का मॉनिटाइजेशन रोका जा सकता है, उनकी पोस्ट की पहुंच कम की जाएगी और उन्हें फेसबुक की सिफारिशों से हटा दिया जाएगा। मेटा अब डुप्लिकेट वीडियो की पहचान कर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी घटाएगा, ताकि असली क्रिएटर्स को क्रेडिट और व्यूज मिल सकें।

एआई से बने 'सस्ते' वीडियो पर भी नजर

हालांकि मेटा ने सीधे एआई स्लोप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने कहा है कि सिर्फ क्लिप्स जोड़कर या वॉटरमार्क लगाकर कंटेंट बनाने से बचें। कंपनी ने ऑथेंटिक स्टोरीटेलिंग पर फोकस करने की सलाह दी है और चेतावनी दी है कि जिन वीडियो में कोई ठोस वैल्यू नहीं होगी, वे भी निगरानी में रहेंगे। यानी एआई से बने रिपिटेटिव वीडियो पर भी कार्रवाई हो सकती है।

मेटा ने कहा कि ये बदलाव धीरे–धीरे लागू होंगे, जिससे क्रिएटर्स को खुद को एडजस्ट करने का वक्त मिलेगा। अगर कोई क्रिएटर समझना चाहता है कि उसके कंटेंट की रीच क्यों घट रही है, तो वह डैशबोर्ड में जाकर नए पोस्ट–लेवल इनसाइट्स देख सकता है। इसके अलावा सपोर्ट सेक्शन में यह भी पता चलेगा कि वह किसी पेनल्टी के खतरे में है या नहीं।

एआई के कारण सोशल मीडिया पर नकली, बार–बार दोहराया गया और कम गुणवत्ता वाला कंटेंट तेजी से बढ़ रहा है। यूट्यूब पहले ही इस पर सख्ती का ऐलान कर चुका है और अब मेटा भी अपने प्लेटफॉर्म्स की क्वॉलिटी बरकरार रखने के लिए ऐसा कर रहा है।

मेटा का यह कदम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक साफ संदेश है कि अगर वे सिर्फ कॉपी–पेस्ट या रिपीटेड एआई कंटेंट शेयर करेंगे, तो उन्हें फेसबुक पर सजा भुगतनी पड़ेगी। अब सोशल मीडिया पर टिके रहने का एक ही तरीका है, असली और मूल्यवान कंटेंट बनाना।

कहां रुकेंगे अखिलेश

ब्राह्मण-ठाकुर के बाद अब साधु-संतों का अपमान

अखिलेश जब भी मुंह खोलते हैं उनके मुंह से सनातन के खिलाफ जहर ही निकलता है। कभी वह ब्राहमणों को कोसते हैं तो कभी ठाकुरों के लिये अपमानजनक भाषा बोलते हैं।

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने में लगे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जिस तरह से हिन्दू और सनातन विरोधी सियासत कर रहे हैं, उससे लगता है कि अखिलेश की समाजवादी पार्टी के पास सत्ता हासिल करने के लिये हिन्दुओं को लड़वाने और उनके धर्माचार्यों को भला–बुरा कहने के अलावा कोई और एजेंडा नहीं बचा है। अखिलेश जब भी मुंह खोलते हैं उनके मुंह से सनातन के खिलाफ जहर ही निकलता है। कभी वह ब्राहमणों को कोसते हैं तो कभी ठाकुरों के लिये अपमानजनक भाषा बोलते हैं। अखिलेश पीडीए के माध्यम से पिछड़ा,दलित और अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिये ब्राहमण, ठाकुरों के लिये अपशब्द कहते रहते थे,लेकिन अब तो वह हिन्दुओं के धर्माचार्यों के खिलाफ भी हमलावार नजर आ रहे हैं।

इस बार विवाद का केंद्र थे अखिलेश यादव और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। बात शुरू हुई थी इटावा में गैर–ब्राह्मण कथावाचकों को लेकर छिड़े एक विवाद से, जो धीरे–धीरे सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया। अखिलेश यादव, जो हमेशा से अपनी तीखी बयानबाजी और रणनीतिक सियासत के लिए जाने जाते हैं, इस बार धीरेंद्र शास्त्री को निशाने पर ले बैठे। उनके एक बयान ने न केवल साधु–संतों की नजरों में उन्हें चर्चा का विषय बना दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

बात इतनी बढ़ गई कि मामला अब डीएनए टेस्ट तक जा पहुंचा।

यह सब तब शुरू हुआ जब अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ कथावाचक अपनी कथाओं के लिए मोटी रकम वसूलते हैं, और खास तौर पर धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वह अंडर टेबल लाखों रुपये लेते हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि 50 लाख रुपये की फीस लेकर कथाएं करने वाले इन बाबाओं को आम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके इस बयान ने तुरंत ही सियासी तूफान खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी के इस बयान को बीजेपी ने सनातन धर्म और हिंदू भावनाओं पर हमला करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव का असली मकसद हिंदुओं को बांटना और सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है।

धीरेंद्र शास्त्री ने भी इस हमले का जवाब देने में देर नहीं की। उन्होंने अखिलेश के बयान को न केवल अपमानजनक बताया, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, हिंदू होकर तुम्हें हमसे दिक्कत है, तो पहले तुम अपना डीएनए टेस्ट करवाओ।

जो हिंदू का नहीं, वो किसी का नहीं। इस बयान ने विवाद को और हवा दे दी। सोशल मीडिया पर यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ लोग धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में उतरे, तो कुछ ने अखिलेश यादव की इस रणनीति को सियासी चाल करार दिया।

बहरहाल, अखिलेश यादव का यह हमला

उन्होंने कहा कि कुछ कथावाचक अपनी कथाओं के लिए मोटी रकम वसूलते हैं, और खास तौर पर धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वह अंडर टेबल लाखों रुपये लेते हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि 50 लाख रुपये की फीस लेकर कथाएं करने वाले इन बाबाओं को आम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते।

कोई नई बात नहीं थी। वह पहले भी बीजेपी और साधु–संतों के प्रभाव को लेकर तंज कस चुके हैं। लेकिन इस बार उनका निशाना धीरेंद्र शास्त्री पर था, जो हाल के वर्षों में हिंदू एकता और सनातन धर्म के प्रचार के लिए चर्चित रहे हैं। अखिलेश का आरोप था कि कुछ बाबा धर्म की आड़ में धंधा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब बीजेपी की उस कवायद का हिस्सा है, जो हिंदू एकता के नाम पर सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने इसे साहसी कदम बताया, जबकि बीजेपी ने इसे धर्म–विरोधी करार दिया।

विवाद तब और गहरा गया जब बीजेपी के कुछ नेताओं ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने तो उल्टे अखिलेश की तारीफ कर डाली, लेकिन अपनी शैली में। उन्होंने कहा कि अखिलेश धर्म के विरोधी नहीं हैं, उनकी मजबूरी है। यह बयान भी चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि यह बीजेपी के अपने रुख से थोड़ा हटकर था। दूसरी ओर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता अरुण राजभर ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि वह ब्राह्मण बनाम यादव का मुद्दा उठाकर अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) मॉडल को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर भी यह जंग कम नहीं थी। कुछ यूजर्स ने अखिलेश के बयान को सनातन धर्म पर हमला बताया, तो कुछ ने इसे धीरेंद्र शास्त्री जैसे बाबाओं की असलियत उजागर करने की कोशिश करार दिया। वहीं, दूसरी ओर, धीरेंद्र शास्त्री के समर्थकों ने कहा कि अखिलेश जानबूझकर हिंदू एकता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि संगठित हिंदू उनके सियासी भविष्य के लिए खतरा बन सकता है।

इस पूरे विवाद में एक बात साफ थी कि यह केवल धीरेंद्र शास्त्री और अखिलेश यादव की तकरार नहीं थी। यह सियासत, धर्म, और जाति का एक जटिल मिश्रण था, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहरे तक पैठ रखता है। अखिलेश यादव का यह बयान उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसके जरिए वह बीजेपी के हिंदू कार्ड को चुनौती देना चाहते हैं। दूसरी ओर, धीरेंद्र शास्त्री का जवाब उनके उस छवि को और मजबूत करता है, जिसमें वह सनातन धर्म के रक्षक के रूप में देखे जाते हैं।

जैसे–जैसे यह विवाद बढ़ता गया, साधु–संतों का एक वर्ग भी इस बहस में कूद पड़ा। कुछ संतों ने अखिलेश के बयान को अपमानजनक बताया, तो कुछ ने इसे सियासी हथकंडा करार दिया। इस बीच, धीरेंद्र शास्त्री ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि वह किसी भी सियासी दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'हमारे लिए कोई पक्ष–विपक्ष नहीं है। हम तो सनातन धर्म की बात करते हैं।' लेकिन उनके इस बयान ने भी विवाद को पूरी तरह शांत नहीं किया।

अखिलेश को बड़ा झटका देने की तैयारी में ब्राह्मण समाज

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने नए आवास और पार्टी कार्यालय, जिसे उन्होंने पीडीए भवन नाम दिया, का उद्घाटन और गृह प्रवेश किया। लेकिन इस भव्य आयोजन के बीच एक सवाल ने सबका ध्यान खींचा, अखिलेश ने गृह प्रवेश की पूजा के लिए काशी के ब्राह्मण विद्वानों को आमंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के किसी विद्वान को क्यों नहीं बुलाया?

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो समाजवादी पार्टी (सपा) का गढ़ माना जाता है, 3 जुलाई 2025 को एक बार फिर सुर्खियों में था। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने नए आवास और पार्टी कार्यालय, जिसे उन्होंने पीडीए भवन नाम दिया, का उद्घाटन और गृह प्रवेश किया। यह भवन अनवरगंज में 72 बिस्वा जमीन पर बना है, जिसमें अखिलेश का निजी निवास, पार्टी कार्यालय, और समर्थकों के लिए एक बड़ा हॉल शामिल है। लेकिन इस भव्य आयोजन के बीच एक सवाल ने सबका ध्यान खींचा, अखिलेश ने गृह प्रवेश की पूजा के लिए काशी के ब्राह्मण विद्वानों को आमंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समुदाय के किसी विद्वान को क्यों नहीं बुलाया? यह सवाल न केवल सियासी गलियारों में, बल्कि सोशल मीडिया और स्थानीय जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया। बात ब्राह्मण समाज की नाराजगी की कि जाये तो ब्राह्मण सभा ने सपा कार्यालय और आवास के गृह प्रवेश के लिये गये ब्राह्मणों को अपने समाज से निकाल दिया है। ब्राह्मणों की यह नाराजगी सपा को 2027 के चुनाव में भारी पड़ सकती है, यूपी में करीब 10 प्रतिशत ब्राह्मण हैं।

आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का यह नया कार्यालय 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अखिलेश ने इसे पीडीए भवन नाम देकर अपनी रणनीति को स्पष्ट कर दिया। पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित, और अल्पसंख्यक सपा की राजनीतिक रणनीति का आधार रहा है, जिसने 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को 37 सीटें दिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विजय रथ को रोकने में मदद की। अखिलेश ने उद्घाटन समारोह में कहा, ष्पीडीए की एकता ही हमें 2027 में सत्ता दिलाएगी।ष इस भवन को न केवल एक कार्यालय, बल्कि एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां युवाओं को समाजवादी विचारधारा से जोड़ा जाएगा।

लेकिन इस आयोजन की चमक उस समय फीकी पड़ गई, जब यह खबर आई कि अखिलेश ने गृह प्रवेश की पूजा के लिए काशी के ब्राह्मण विद्वानों को बुलाने की इच्छा जताई थी, लेकिन वे नहीं आए। सूत्रों के अनुसार, काशी के पंडितों ने इटावा में हाल ही में हुए एक विवाद, जिसे श्इटावा कथावाचक कांडश कहा जा रहा है, के कारण नाराजगी जताते हुए पूजा कराने से मना कर दिया। इस कांड में अखिलेश के कुछ बयानों को ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ माना गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर दान–दक्षिणा और पूजा–पाठ की परंपराओं पर सवाल

उठाए थे।

अखिलेश ने अंततः स्थानीय पंडितों से पूजा करवाई, और कुछ स्रोतों के अनुसार, पुजारी चंदन कुशवाहा ने इस कार्य को संपन्न किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि पीडीए भवन के उद्घाटन जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर, जब अखिलेश अपनी पीडीए रणनीति को और मजबूत करने की बात कर रहे थे, तब उन्होंने पीडीए समुदाय के किसी विद्वान को पूजा के लिए क्यों नहीं चुना? यह सवाल न केवल उनके विरोधियों, बल्कि उनके समर्थकों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे अखिलेश की रणनीति में विरोधाभास बताया। एक यूजर ने लिखा, ष्भवन का नाम तो रख दिया, लेकिन पूजा ब्राह्मणों से ही करवानी है। क्या पीडीए में कोई विद्वान नहीं था?ष एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए कहा, ष्अखिलेश जी को कोई पीडीए का पंडित नहीं मिला क्या? कथनी और करनी में अंतर साफ दिखता है।ष इन टिप्पणियों ने सपा के पीडीए फार्मूले पर सवाल उठाए, जिसे अखिलेश ने हाल के वर्षों में अपनी पार्टी की छवि को यादव–मुस्लिम से हटाकर व्यापक बनाने के लिए अपनाया था।

आजमगढ़ में पूजा के लिए ब्राह्मण विद्वानों को बुलाने की कोशिश को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा

बात ब्राह्मण समाज की नाराजगी की कि जाये तो ब्राह्मण सभा ने सपा कार्यालय और आवास के गृह प्रवेश के लिये गये ब्राह्मणों को अपने समाज से निकाल दिया है ब्राह्मणों की यह नाराजगी सपा को 2027 के चुनाव में भारी पड़ सकती है, यूपी में करीब 10 प्रतिशत ब्राह्मण हैं।

है। अखिलेश शायद यह संदेश देना चाहते थे कि उनकी पार्टी सभी समुदायों को साथ लेकर चल रही है। लेकिन काशी के पंडितों की अनुपस्थिति और स्थानीय पंडितों द्वारा पूजा करवाने ने इस संदेश को कमजोर कर दिया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश का यह कदम उनकी पीडीए रणनीति को मजबूत करने का प्रयास था, लेकिन यह उल्टा पड़ गया।

इस आयोजन को और चर्चा में लाने वाला एक अन्य पहलू था ब्राह्मण महासभा और विश्व हिंदू महासंघ के सदस्यों का विरोध। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अखिलेश के खिलाफ काले झंडे लहराए और उन पर ब्राह्मण समुदाय की छवि खराब करने का आरोप लगाया। इसके अलावा, एक सुरक्षा चूक ने भी सुर्खियां बटोरीं, जब एक युवक बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के करीब पहुंच गया। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया, लेकिन इस घटना ने अखिलेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए।इन विवादों के बावजूद, पीडीए भवन का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भवन न केवल अखिलेश का दूसरा घर है, बल्कि पूर्वांचल में सपा की सियासी रणनीति का केंद्र भी बनेगा। अखिलेश ने अपने भाषण में बीजेपी पर जमकर हमला बोला और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय अपनी सरकार को दिया। उन्होंने कहा, लखनऊ से आजमगढ़ पहुंचने में उतना ही समय लगता है, जितना सैफई। यह हमारे द्वारा बनाए गए एक्सप्रेसवे की बदौलत है।बहरहाल, आजमगढ़ में पीडीए भवन का उद्घाटन और गृह प्रवेश एक सियासी मास्टर स्ट्रोक हो सकता था, लेकिन ब्राह्मण विद्वानों की अनुपस्थिति और पीडीए समुदाय के विद्वानों को न बुलाने का फैसला सवालों के घेरे में आ गया। जहां वे एक तरफ अपने मूल समर्थक वर्ग को मजबूत करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ सवर्ण वोटरों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। 2027 के चुनावों में यह रणनीति कितनी कारगर होगी, यह तो समय ही बताएगा।

बाजार दिखा बड़ा लेकिन खरीदार है छोटा

क्या टिक पाएगी टेस्ला इंडिया में?

टेस्ला यानी उस सपने का नाम, जो अमेरिका में नवाचार की पहचान बन चुका है। लेकिन भारत में यह सपना साकार होगा या फिर वही हश्र होगा जो पहले भी कई विदेशी कंपनियों का हुआ, यही सवाल आज देश का हर गंभीर ऑटो विशेषज्ञ पूछ रहा है।

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

मुंबई के बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स की चमचमाती सड़कें, शीशे के भव्य शोरूम में खड़ी एक कार और बाहर भीड़ का उत्साह 15 जुलाई की सुबह कुछ ऐसी ही थी, जब भारत में टेस्ला ने आधिकारिक तौर पर कदम रखा। टेस्ला यानी उस सपने का नाम, जो अमेरिका में नवाचार की पहचान बन चुका है। लेकिन भारत में यह सपना साकार होगा या फिर वही हश्र होगा जो पहले भी कई विदेशी कंपनियों का हुआ, यही सवाल आज देश का हर गंभीर ऑटो विशेषज्ञ पूछ रहा है। टेस्ला की मॉडल Y भारत में लॉन्च हुई है, जिसकी कीमत 60 लाख से 70 लाख के बीच है। यह गाड़ी आम आदमी के सपनों से कहीं दूर है, और इसीलिए यह चर्चा का विषय बन गई है। भारत में जहां कारों की औसत कीमत 11.5 लाख है, वहीं टेस्ला की शुरुआती कीमत छह गुना अधिक है। सवाल यह नहीं कि टेस्ला महंगी क्यों है, सवाल यह है कि भारत जैसे मूल्य–संवेदनशील बाजार में क्या वह टिक पाएगी?

भारत में गाड़ी खरीदना केवल यात्रा का जरिया नहीं, यह स्टेटस सिंबल भी है। लेकिन स्टेटस के साथ–साथ भारतीय ग्राहक "वैल्यू फॉर मनी" भी चाहता है। भारत में आज भी एसयूवी सेक्टर में 20–30 लाख की रेंज में टाटा, महिंद्रा और हुंडई जैसी कंपनियों का बोलबाला है। टेस्ला अगर इस रेंज में आती तो शायद बड़ी हलचल मचती, लेकिन 60 लाख से ऊपर की रेंज में वो खरीदारों का एक सीमित तबका ही पकड़ सकती है। और यह सीमित तबका भी टेस्ला के लिए आसान नहीं होगा। भारत में मर्सिडीज–बेंज, बीएमडब्ल्यू और पोर्शे पहले से इस प्रीमियम सेगमेंट में मौजूद हैं। साल 2024 में भारत में 50 लाख से ऊपर की गाड़ियों की हिस्सेदारी मात्र 1 से 1.5 प्रतिशत थी। यानी 100 में से सिर्फ एक या दो खरीदार ही इस रेंज में खर्च करते हैं। टेस्ला को इन्हीं के बीच अपनी जगह बनानी होगी।

यही नहीं, भारत की ईवी नीति और इंपोर्ट टैक्स भी टेस्ला के लिए बड़ी चुनौती हैं। फिलहाल जो मॉडल लॉन्च किए गए हैं, वे चीन की शंघाई फैक्ट्री से आयातित हैं। और भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 70: से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। यही कारण है कि टेस्ला की कीमतें भारत में दो गुना हो जाती हैं। अगर कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती है और सरकार की नई ईवी नीति के तहत 4,150 करोड़ का निवेश करती है, तो उसे इंपोर्ट ड्यूटी में राहत मिल सकती है। लेकिन मस्क इस पर अब तक कोई साफ संकेत नहीं दे पाए हैं। अब बात करें ब्रांड के भावनात्मक पक्ष की। भारत में आईफोन जैसे महंगे ब्रांड्स की

अब सवाल यह भी है कि क्या भारत का चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर टेस्ला जैसे ब्रांड को सपोर्ट करने के लिए तैयार है? फिलहाल नहीं। टेस्ला ने भले ही मुंबई और दिल्ली में सुपरचार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना बनाई हो, लेकिन पूरे देश में नेटवर्क बनाना एक लंबी प्रक्रिया है। और जब तक यह नेटवर्क तैयार नहीं होता, तब तक टेस्ला का बाजार केवल दिखावे तक सीमित रहेगा।

भी सीमित पहुंच है। आज भी भारत में एप्पल की बाजार हिस्सेदारी केवल 7–12 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह 40 प्रतिशत के आसपास है। इसका सीधा अर्थ है कि भारत के मध्यम वर्ग में महंगे ब्रांड्स का क्रेज तो है, लेकिन जेब उतनी मजबूत नहीं। ऐसे में टेस्ला को भी वही चुनौती झेलनी होगी, जो एप्पल झेल रही है, "ब्रांड दिखे, पर बिके नहीं।" उद्योग जगत भी इस एंट्री को लेकर सतर्क है। एक प्रमुख भारतीय ऑटोमोबाइल ग्रुप के अध्यक्ष ने तो एलन मस्क को सोशल मीडिया पर चुनौती देते हुए लिखा ष्चार्जिंग स्टेशन पर मिलते हैं! "यह सिर्फ एक मजाक नहीं, बल्कि एक सीधा संदेश है कि टेस्ला को भारतीय ब्रांड्स हल्के में नहीं लेने वाले। टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियां पहले ही 10 से 25 लाख की रेंज में ईवी गाड़ियाँ उपलब्ध करा रही हैं, जो आम भारतीयों की जरूरत और बजट दोनों से मेल खाती हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या भारत का चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर टेस्ला जैसे ब्रांड को सपोर्ट करने के लिए तैयार है? फिलहाल नहीं। टेस्ला ने भले ही मुंबई और दिल्ली में सुपरचार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना बनाई हो, लेकिन पूरे देश में नेटवर्क बनाना एक लंबी प्रक्रिया है। और जब तक यह नेटवर्क तैयार नहीं होता, तब तक टेस्ला का बाजार केवल दिखावे तक सीमित रहेगा। टेस्ला का भविष्य इस पर भी निर्भर करेगा कि वह भारतीय ग्राहकों के लिए क्या पेशकश करती है। अगर टेस्ला भविष्य में 40–45 लाख की रेंज में कोई मॉडल लाती है, तो वह मिड प्रीमियम ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है। ये वही ग्राहक हैं जो 30 लाख की गाड़ी खरीदने की हैसियत रखते हैं और ब्रांड वैल्यू के लिए थोड़ा और खर्च करने को तैयार रहते हैं। लेकिन जब सामने टाटा, महिंद्रा और हुंडई जैसे भरोसेमंद ब्रांड हों, तो टेस्ला को केवल ब्रांड इमेज के सहारे सफलता नहीं मिलेगी।

इतिहास भी यही कहता है। हर्ले डेविडसन, शेव्रले और फोर्ड जैसी कंपनियों ने भी भारत में धमाकेदार एंट्री की थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। वजह साफ थी भारतीय बाजार को समझने में चूक। सिर्फ नाम और टेक्नोलॉजी से भारत में गाड़ी नहीं बिकती, यहां लोगों की जरूरत, खर्च की सीमा और सेवा नेटवर्क की अहम भूमिका होती है। भारत में ईवी का भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन अभी शुरुआती दौर में है। 2025 तक कुल गाड़ियों की बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी केवल 4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। ऐसे में टेस्ला को जल्दबाजी नहीं, बल्कि रणनीति से काम लेना होगा। उसे भारत के लिए खास मॉडल, कीमत और सर्विस नीति बनानी होगी। टेस्ला की भारत में एंट्री एक नई शुरुआत है, लेकिन इसका भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि क्या एलन मस्क भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक साझेदार मानते हैं। अगर वह भारत में उत्पादन, रोजगार और तकनीक साझा करते हैं, तो उन्हें भारत का दिल भी मिलेगा और बाजार भी। वरना यह एंट्री भी एक शानदार लेकिन अल्पकालिक तमाशा बनकर

तेल पर चलेगा अमेरिका का डंडा या भारत की कूटनीति?

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के महासचिव मार्क रुटे ने जिस तरह भारत समेत कई देशों को धमकाया है, उसने नई बहस छेड़ दी है कि क्या भारत अब भी रूस से सस्ता तेल खरीद पाएगा या नहीं। सबसे पहले अमेरिका का प्लान समझिए।

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

रूस–यूक्रेन युद्ध को तीन साल होने को हैं, लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब ये सिर्फ यूरोप के दो देशों की जंग नहीं रही, बल्कि एक ऐसा शतरंज बन गई है जिसमें अमेरिका, नाटो, चीन और भारत जैसे बड़े खिलाड़ी भी अपनी–अपनी चाल चल रहे हैं। ताजा हालात में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के महासचिव मार्क रुटे ने जिस तरह भारत समेत कई देशों को धमकाया है, उसने नई बहस छेड़ दी है कि क्या भारत अब भी रूस से सस्ता तेल खरीद पाएगा या नहीं। सबसे पहले अमेरिका का प्लान समझिए। अमेरिका में एक नया बिल 'सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025' लाया गया है, जिसके तहत जो देश रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदते रहेंगे, उन पर अमेरिका में अपने सामान के निर्यात पर 500 प्रतिशत तक का टैक्स लगाया जाएगा। मतलब साफ है रूस से तेल लो और अमेरिका को अपने सामान मत बेचो। ये सीधी धमकी भारत जैसे देशों को दी गई है, जो अब भी रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं।

भारत के लिए यह कोई छोटी बात नहीं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। 2021 में भारत रूस से अपनी जरूरत का सिर्फ 1 प्रतिशत तेल लेता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही रूस ने एशियाई देशों को सस्ता तेल ऑफर किया और भारत ने इसका फायदा उठाया। आज भारत अपनी जरूरत का करीब 35 प्रतिशत तेल रूस से ले रहा है। इससे भारत को सीधे दो फायदे हुए पेट्रोल–डीजल की कीमत काबू में रहीं और डॉलर में भुगतान की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार पर भी ज्यादा दबाव नहीं पड़ा। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि या तो रूस से दूरी बना लो या फिर भारी सेकंडरी टैरिफ झेलो। ट्रंप ने रूस को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर पुतिन ने युद्ध नहीं रोका तो न सिर्फ रूस बल्कि उसके दोस्तों पर भी सजा बरसेगी। नाटो चीफ मार्क रुटे ने तो दिल्ली, बीजिंग और ब्राजीलिया को सीधा नाम लेकर चेतावनी दे दी अगर पुतिन को नहीं मनाओगे तो ये झटका सीधे तुम पर पड़ेगा।

अब सवाल है क्या भारत डर जाएगा? अभी तक के संकेत तो यही बताते हैं कि भारत फिलहाल कोई जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेने वाला। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने साफ कहा कि भारत किसी एक देश के कहने पर अपनी एनर्जी पॉलिसी नहीं बदलेगा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी अमेरिका को करारा जवाब दिया अगर भारत रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदता तो पूरी दुनिया में तेल

की कीमतें 120–130 डॉलर प्रति बैरल पहुंच जातीं, जिससे यूरोप और अमेरिका की जनता भी महंगाई से कराह उठती। पुरी की इस बात में दम है, क्योंकि रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश है। अगर उसे ग्लोबल मार्केट से हटा दिया जाए तो सप्लाई में करीब 10: की कमी आ जाएगी। इसका मतलब पेट्रोल–डीजल इतना महंगा होगा कि भारत से लेकर यूरोप–अमेरिका तक आम आदमी परेशान हो जाएगा।

अब अमेरिका का प्लान सिर्फ रूस की कमर तोड़ना नहीं है। असली मकसद यह भी है कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे बड़े ग्राहक रूस से दूर हो जाएं ताकि पुतिन पर दबाव पड़े। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। भारत ने रूस के अलावा मिडिल ईस्ट के देशों से भी डील कर रखी है, ताकि अगर कभी रूस से सप्लाई रोकी जाए तो सऊदी अरब, यूएई जैसे देश तुरंत तेल की कमी पूरी कर सकें। पर इसमें दिक्कत ये है कि रूस का तेल बाकी सप्लायर्स से काफी सस्ता है। अगर भारत रूस से तेल लेना बंद करेगा तो उसकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और आम आदमी की कमर टूटेगी। भारत के लिए दूसरी चुनौती उसके निर्यात को लेकर है। अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी, ऑटो पार्ट्स इन सबका बड़ा हिस्सा अमेरिका जाता है। अगर अमेरिका 500: टैक्स लगा देगा तो भारत के सामान की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि अमेरिकी कंपनियां

भारत के लिए यह कोई छोटी बात नहीं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। २०२१ में भारत रूस से अपनी जरूरत का सिर्फ १ प्रतिशत तेल लेता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही रूस ने एशियाई देशों को सस्ता तेल ऑफर किया और भारत ने इसका फायदा उठाया।

और ग्राहक उसे खरीदना छोड़ देंगे। इससे करोड़ों लोगों की नौकरियां और देश की कमाई दोनों पर असर पड़ेगा।

अब ये भी देखिए कि ट्रंप इस बिल को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि रूस को दबाव में लाकर पुतिन को युद्धविराम पर मजबूर करें। इसके लिए वो भारत जैसे देशों को गले से पकड़ना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप भी जानते हैं कि भारत को पूरी तरह मजबूर करना आसान नहीं है। क्योंकि भारत को अगर ज्यादा दबाया गया तो वो चीन या रूस के और करीब जा सकता है। इससे अमेरिका की इंडो–पैसिफिक रणनीति को बड़ा झटका लगेगा। अमेरिका एशिया में चीन को रोकने के लिए भारत को अहम साझेदार मानता है। ऐसे में भारत को नाराज करना खुद अमेरिका के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इधर भारत भी चुपचाप नहीं बैठा है। मोदी सरकार पहले ही सऊदी अरब, यूएई और ब्राजील से अतिरिक्त सप्लाई पर बातचीत कर रही है। अगर कभी रूस से सप्लाई कम भी करनी पड़ी तो भारत के पास बैकअप प्लान रहेगा। लेकिन ये बैकअप प्लान भी महंगा पड़ेगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों का तेल रूस जितना सस्ता नहीं है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत शायद सीधे तौर पर रूस से हाथ नहीं खींचेगा, लेकिन रूस पर अपनी निर्भरता थोड़ा घटा सकता है। मिडिल ईस्ट से थोड़ा ज्यादा तेल लेकर अमेरिका को यह दिखा सकता है कि उसने दबाव में कुछ 'संतुलन' किया है। लेकिन पूरी तरह रूस से दूरी फिलहाल नामुमकिन लगती है। रूस भी अपनी चालें चल रहा है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन में तब तक जंग जारी रखेंगे जब तक पश्चिम उनकी शर्तों पर शांति समझौते के लिए राजी नहीं होता। पुतिन जानते हैं कि भारत और चीन जैसे देशों के रहते उन पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंध पूरी तरह असर नहीं दिखा पाएंगे। यही वजह है कि रूस अब एशियाई बाजारों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और तेल–गैस के अलावा कोयला, खाद्यान्न और यूरेनियम के सौदे भी इन्हीं देशों के साथ कर रहा है।

अब सवाल अगले 50 दिन में क्या होगा? क्या रूस युद्ध रोक देगा? क्या भारत को सच में 500 प्रतिशत सेकंडरी टैरिफ झेलना पड़ेगा? या अमेरिका दबाव डालने के बाद पीछे हट जाएगा? फिलहाल ज्यादातर जानकार मानते हैं कि अमेरिका धमकी देकर सौदेबाजी करेगा। ट्रंप का मकसद यही है कि उसे राष्ट्रपति के हाथ में पूरा कंट्रोल मिले कि कब टैरिफ लगाना है और कब छूट देनी है। इससे वो भारत जैसे देशों को बातचीत की टेबल पर लाकर अपनी शर्तें मनवा सके। भारत के लिए यह वक्त बड़ा सावधानी से कदम उठाने का है। उसे एक तरफ रूस से सस्ता तेल चाहिए, ताकि महंगाई काबू में रहे, दूसरी तरफ अमेरिका से दोस्ती भी चाहिए ताकि निर्यात और रक्षा साझेदारी पर असर न पड़े। ऐसे में मोदी सरकार की कूटनीति अब असली अग्निपरीक्षा में है। एक बात साफ है इस बार लड़ाई सिर्फ टैंक और मिसाइलों से नहीं लड़ी जा रही, असली जंग तेल और गैस पर है। दुनिया देख रही है कि भारत जैसे देश इस जंग में किसे चुनते हैं सस्ती ऊर्जा या अमेरिकी बाजार। भारत ने इशारा दे दिया है कि उसका झुकाव अपनी जनता की भलाई

भारत में 50% वाहनों के पास बीमा नहीं, 30% से भी कम गाड़ियों के पास प्रदूषण प्रमाण पत्र

देश में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उनके लिए जरूरी कानूनी दस्तावेज जैसे बीमा (इंश्योरेंस) और प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUCC) की अनदेखी हो रही है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 50 प्रतिशत से ज्यादा वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या दोपहिया वाहनों की है।

कुछ राज्यों में प्रदूषण प्रमाण पत्र की स्थिति बेहद खराब

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रदूषण प्रमाण पत्र की अनुपालन दर 30: से भी कम है। यह दर्शाता है कि गाड़ियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन नियमों का पालन नहीं हो रहा।

दक्षिण भारत में स्थिति थोड़ी बेहतर

रिपोर्ट में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश और केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र का अनुपालन लगभग 9.6 प्रतिशत है, जबकि उत्तर भारत में यह दर सिर्फ 5.6 प्रतिशत है। उत्तर भारत में सबसे बड़ी समस्या एक्सपायर्ड बीमा की है, जबकि दक्षिण भारत में पीयूसीसी का अभाव अधिक है।

महाराष्ट्र सबसे पीछे, राजस्थान कुछ बेहतर

महाराष्ट्र में नियमों के अनुपालन की दर मात्र 1.9 प्रतिशत है, जो देश में सबसे कम है। राजस्थान में यह दर 6.74 प्रतिशत है, जिससे साफ है कि अलग–अलग राज्यों में वाहन नियमों को लेकर स्थिति अलग–अलग है।

फास्टैग का उपयोग बढ़ा, लेकिन दस्तावेजों की लापरवाही जारी

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जून 2024 से जून 2025 के बीच फास्टैग टोल कलेक्शन में 17.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और औसतन फास्टैग वॉलेट बैलेंस 408 रुपये रहा। लोग डिजिटल पेमेंट अपना रहे हैं, लेकिन जरूरी दस्तावेजों के मामले में लापरवाही कर रहे हैं।

ट्रैफिक चालान का भारी बोझ

देश में ट्रैफिक चालान को लेकर भी चिंता की स्थिति है। 2015 से अब तक कुल 5. 11 लाख करोड़ रुपये के चालान काटे जा चुके हैं, लेकिन इनमें से केवल 1.92 लाख करोड़ रुपये की ही वसूली हो सकी है। बाकी 3.18 लाख करोड़ रुपये अदालतों में लंबित हैं और लगभग 7.69 करोड़ चालान कोर्ट में अटके हुए हैं। यह रिपोर्ट साफ तौर पर दिखाती है कि भारत में वाहन संख्या के मुकाबले कानूनों का पालन बेहद कमजोर है। लोगों को केवल वाहन खरीदने की नहीं, बल्कि उसे कानूनी रूप से जिम्मेदारी के साथ चलाने की जरूरत है।

क्या जन्म का महीना मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? रिपोर्ट में हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा

- **क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा दूसरों की तुलना में अधिक क्यों होता है?**
- **एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, जन्म के महीनों और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक दिलचस्प संबंध सामने आया है।**

मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं अब दुनियाभर में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी हैं। बीते कुछ वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन तनाव, चिंता और अवसाद जैसे मामलों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह समस्या युवाओं को अधिक प्रभावित कर रही है, यहां तक कि 20 वर्ष से कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि दुनियाभर में हर आठवां व्यक्ति किसी न किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहा है। तेज रफ्तार जीवनशैली, सोशल मीडिया का प्रभाव, अकेलापन, आर्थिक बोझ और भावनात्मक असंतुलन जैसे कारक मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालते हैं।

क्या जन्म के महीने से जुड़ा है मानसिक स्वास्थ्य का खतरा?

एक नए शोध में दावा किया गया है कि कुछ खास महीनों में जन्म लेने वाले लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा अधिक हो सकता है। विशेष रूप से गर्मियों के महीनों जून, जुलाई और अगस्त में जन्मे पुरुषों में डिप्रेशन की संभावना ज़्यादा पाई गई है।

यह अध्ययन कनाडा की क्वांटलेन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया, जिसे 'पल्सवन जर्नल' में प्रकाशित किया गया। हालांकि अध्ययन का सैंपल साइज सीमित था, लेकिन इसके निष्कर्षों ने विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है।

शोध में क्या मिला?

शोध में 303 प्रतिभागियों (106 पुरुष और 197 महिलाएं) की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन PHQ–9 (अवसाद) और GAD–7 (चिंता) स्केल से किया गया। इन प्रतिभागियों की औसत उम्र 26 साल थी। इनके जन्म माह का विश्लेषण कर यह जांचा गया कि क्या जन्म का मौसम मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। रिपोर्ट में नतीजे चौंकाने वाले थे–

- **84 प्रतिशत प्रतिभागियों में डिप्रेशन के लक्षण**
- **66 प्रतिशत में स्ट्रेस के लक्षण**

विशेष रूप से गर्मियों में जन्मे 78 पुरुषों में हल्के से गंभीर स्तर के डिप्रेशन के संकेत मिले। जबकि सर्दियों में जन्मे 67, वसंत में जन्मे 58 और शरद ऋतु में जन्मे 68 पुरुषों में ऐसे लक्षण अपेक्षाकृत कम देखे गए।

अध्ययन में पता चला है कि जन्म के समय की पर्यावरणीय परिस्थितियां, जैसे प्रकाश, तापमान, और गर्भावस्था के दौरान मातृ स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही, बचपन या गर्भकाल के दौरान मौसमी संक्रमणों का असर भी मानसिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि बच्चे के विकास के दौरान आसपास का वातावरण मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। इस अध्ययन से यह संकेत मिला कि गर्मियों में जन्मे बच्चों में आगे चलकर डिप्रेशन जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इसके लिए और गहन शोध की आवश्यकता है।

योगी की सख्ती से यूपी छोड़ रहे हैं दिग्गज ब्यूरोक्रेट्स

योगी सरकार की कार्यशैली, जिसमें सख्ती और जवाबदेही पर जोर है, ने न केवल नीतिगत फैसलों को प्रभावित किया, बल्कि ब्यूरोक्रेसी के ढांचे और अधिकारियों की भूमिका को भी नया आकार दिया।

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में प्रशासनिक तंत्र हमेशा चर्चा में रहा है। योगी सरकार की कार्यशैली, जिसमें सख्ती और जवाबदेही पर जोर है, ने न केवल नीतिगत फैसलों को प्रभावित किया, बल्कि ब्यूरोक्रेसी के ढांचे और अधिकारियों की भूमिका को भी नया आकार दिया। पिछले कुछ वर्षों में कई दिग्गज भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों से हटाकर कम प्रभावशाली भूमिकाओं में भेजा गया, जिसे नौकरशाही हलकों में हाशिए पर धकेलने के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही, सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और लगातार प्रशासनिक फेरबदल ने यूपी की ब्यूरोक्रेसी को एक नया चेहरा दिया है।

गौरतलब हो 2022 में सत्ता हासिल करते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रशासनिक अधिकारियों पर सख्त नजर आये थे और यह सिलसिला आज तक जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली में नौकरशाहों से त्वरित परिणाम और पारदर्शिता की अपेक्षा रही है। इस कारण कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से हटाया गया। उदाहरण के लिए, 2006 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को 2025 में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति का हिस्सा थी। अभिषेक प्रकाश जैसे अधिकारियों का निलंबन न केवल उनके करियर पर प्रभाव डालता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि सरकार किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी तरह, 2011 बैच के आईएएस अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडेय, जो उन्नाव में जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत थे, को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया गया। हालांकि, बाद में उनकी बहाली हुई, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयों ने उनकी प्रशासनिक छवि को प्रभावित किया। वैसे प्रशासनिक हलकों में यह भी चर्चा छिड़ी रहती है कि योगी जी के राज में एक खास बिरादरी के अधिकारियों पर ज्यादा विश्वास जताया जा रहा है, भले ही उनकी छवि साफ सुथरी नहीं हो। वैसे ऐसे ही आरोप विपक्ष के नेताओं खास कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लगाते रहे हैं कि योगी सरकार में क्षत्रियवाद बुरी

तरह से हावी है।

वैसे यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी में वरिष्ठ अधिकारियों की कमी भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। पिछले साल एक समाचार पत्र में रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार यूपी में अपर मुख्य सचिव (एसीएस) स्तर के 16 स्वीकृत पदों में से केवल 11 पर ही अधिकारी तैनात थे। इसी तरह, प्रमुख सचिव स्तर पर 36 में से 29 और सचिव स्तर पर 96 में से 58 अधिकारी ही कार्यरत थे। कुल मिलाकर, यूपी में 652 आईएएस अधिकारियों की जरूरत के मुकाबले केवल 560 अधिकारी उपलब्ध हैं। इस कमी का एक कारण यह भी माना जाता है कि कई वरिष्ठ अधिकारी केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। 1989 बैच के भुवनेश कुमार चतुर्वेदी केंद्रीय कृषि विभाग में सचिव बनकर चले गए, जबकि 1991 बैच के कामरान रिजवी और निवेदिता केंद्र में अतिरिक्त सचिव के पद पर हैं। कुछ नौकरशाही हलकों में यह चर्चा है कि योगी सरकार की सख्त कार्यशैली के कारण कई अधिकारी केंद्र की नौकरी को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे यूपी में वरिष्ठ अधिकारियों की कमी और गहरा रही है।

प्रशासनिक फेरबदल योगी सरकार की एक और विशेषता रही है। हाल के वर्षों में सैकड़ों आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इसी वर्ष 22 पीसीएस अधिकारियों को प्रोन्नति देकर आईएएस बनाया गया, जिन्हें जल्द ही नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। इनमें से कुछ को जिलाधिकारी के पद पर तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा, 2024 और 2025 में कई बड़े पैमाने पर तबादले हुए, जिनमें 5 से 15 आईएएस अधिकारियों को एक साथ बदला गया। सितंबर 2024 में प्रनत ऐश्वर्य को मुख्य विकास अधिकारी अंबेडकरनगर से विशेष सचिव नमामि गंगे और संयुक्त प्रबंध निदेशक जल निगम ग्रामीण बनाया गया। इसी तरह, उमेश प्रताप सिंह को भूतत्व खनिकर्म विभाग से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में स्थानांतरित किया गया। इन तबादलों को सरकार की कार्यकुशलता बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जाता है, लेकिन कई बार इन्हें अधिकारियों को हाशिए पर धकेलने के रूप में भी व्याख्या की जाती है।

कई मामलों में, अधिकारियों को कम महत्वपूर्ण विभागों या पदों पर भेजा गया, जिसे नौकरशाही में डिमोशन के रूप में देखा जाता है। लखीमपुर खीरी में खेत की पैमाइश में देरी के एक पुराने मामले में 2024 में आईएएस अधिकारी घनश्याम सिंह सहित तीन पीसीएस अधिकारियों को निलंबित किया गया। हालांकि घनश्याम सिंह को बाद में बहाल कर लिया गया, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयां अधिकारियों की छवि और प्रभाव को कम करती हैं। इसी तरह, 2015 बैच के कुछ अधिकारियों को जिलाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों की रेस में शामिल होने के बावजूद कम प्रभावशाली भूमिकाओं में रखा गया। सूत्रों के अनुसार, प्रणय सिंह, अमनदीप डुली और आलोक यादव जैसे अधिकारियों को जल्द ही जिलाधिकारी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक उनकी तैनाती अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण पदों पर ही रही है।

योगी सरकार की नीतियों ने ब्यूरोक्रेसी में जवाबदेही को बढ़ावा दिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में कई दिग्गज अधिकारियों को हाशिए पर जाने का सामना करना पड़ा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां, जैसे 11 आईएएस अधिकारियों का निलंबन, और लगातार तबादले, ने नौकरशाही में एक तरह का दबाव बनाया है। कुछ अधिकारी इसे सरकार की सख्ती के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ इसे प्रशासन को चुस्त–दुरुस्त करने की रणनीति मानते हैं। इसके बावजूद, यह स्पष्ट है कि योगी सरकार की प्राथमिकता कार्यकुशलता और पारदर्शिता है, जिसके लिए वह किसी भी स्तर पर समझौता करने को तैयार नहीं है।

दूसरी ओर, सरकार की योजनाओं को लागू करने में ब्यूरोक्रेसी की भूमिका अहम रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, और मुफ्त बस सेवा जैसी पहलें नौकरशाही के सहयोग से ही संभव हुई हैं। लेकिन इन योजनाओं को लागू करने में विफलता या देरी ने कई अधिकारियों को सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ा। कुंभ मेला 2025 की तैयारियों के लिए विजय किरन आनंद जैसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं, जबकि कुछ अन्य को कम प्रभावशाली भूमिकाओं में रखा गया। बहरहाल, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बदलाव का यह दौर न केवल प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित कर रहा है, बल्कि अधिकारियों के करियर पथ को भी नया आकार दे रहा है। योगी सरकार की सख्ती और लगातार फेरबदल ने कई दिग्गज आईएएस अधिकारियों को हाशिए पर धकेल दिया है, लेकिन यह भी सच है कि इस प्रक्रिया ने नए और ऊर्जावान अधिकारियों को मौका दिया है। कुल मिलाकर, यूपी की ब्यूरोक्रेसी एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां जवाबदेही और परिणाम सरकार की प्राथमिकता बने हुए हैं।

शिक्षक: ज्ञान के वाहक या वैचारिक प्रचारक

यह भारत में धार्मिक आस्था, शिक्षा, तर्क और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच खिंची उस लकीर का उदाहरण है जो आज की तारीख में लगातार गहरी होती जा रही है। यह मामला दिखाता है कि आज के समय में शिक्षक, विद्यार्थी, समाज और राजनीति के बीच की संवेदनशील रेखाएं कितनी धुंधली होती जा रही हैं।

संजय सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

बरेली के महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज में हिंदी के शिक्षक डॉ. रजनीश गंगवार द्वारा पढ़ी गई कविता "तुम कांवड़ लेने मत जाना" पर मचा बवाल सिर्फ एक कविता पर विवाद नहीं है, बल्कि यह भारत में धार्मिक आस्था, शिक्षा, तर्क और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच खिंची उस लकीर का उदाहरण है जो आज की तारीख में लगातार गहरी होती जा रही है। यह मामला दिखाता है कि आज के समय में शिक्षक, विद्यार्थी, समाज और राजनीति के बीच की संवेदनशील रेखाएं कितनी धुंधली होती जा रही हैं। कविता का मूल भाव यदि देखा जाए, तो छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना था। लेकिन जिस रूप में यह बात कही गई, उसमें धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग इस तरह किया गया कि मामला श्रद्धा और तिरस्कार के बीच फंस गया। कविता की पंक्तियां थीं, "कांवड़ ढोकर कोई डीएम, एसपी नहीं बना है। भांग, धतूरा, गांजा, सुल्फा मद से कोई उद्धार नहीं हुआ है। तुम कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना।" शब्दों की गहराई को देखें तो यह सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि कटाक्ष था। "कांवड़", "गांजा", "धतूरा", "सुल्फा" जैसे शब्दों का संयोजन उस धार्मिक परंपरा पर प्रश्न चिह्न लगाता है जो करोड़ों लोगों के लिए एक श्रद्धा है। कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। इसमें सामूहिकता, अनुशासन, सेवा और संकल्प का भाव होता है। ऐसे में जब एक शिक्षक इसे इस तरह चित्रित करता है कि जैसे यह सिर्फ नशे और फालतूपन का प्रतीक है, तो समाज के एक बड़े हिस्से में आक्रोश पैदा होना स्वाभाविक है।

कविता के पक्ष में यह तर्क दिया जा सकता है कि शिक्षक ने बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए यह उदाहरण दिया। लेकिन क्या प्रेरणा देने के लिए धार्मिक परंपराओं को नीचा दिखाना जरूरी हो जाता है? क्या कोई शिक्षक यह नहीं कह सकता था कि

"शिक्षा ही सर्वोत्तम साधना है" या "ज्ञान का मार्ग ही सफलता का मार्ग है" बिना किसी धर्म, परंपरा या भावना पर कटाक्ष किए? जब बात शिक्षा की होती है, तो तटस्थता सबसे जरूरी तत्व बन जाती है। एक शिक्षक का हर शब्द विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव डालता है, ऐसे में उसकी बातों में संतुलन और संवेदनशीलता दोनों होनी चाहिए।

इस कविता की सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि इसका संदर्भ भले ही शिक्षा था, लेकिन भाषा और प्रतीकों की वजह से यह सीधे धर्म से टकरा गई। और जब मामला धर्म बनाम शिक्षा में तब्दील होता है, तो वह केवल कक्षा तक सीमित नहीं रह जाता। फिर वह समाज की सड़कों पर उतर आता है। यही इस मामले में हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी, एफआईआर दर्ज हुई, शिक्षक को सस्पेंड किया गया और मामला राजनीतिक रंग में रंग गया। यहां यह सवाल उठता है कि क्या हमारे शिक्षक शिक्षा के नाम पर वैचारिक प्रचार कर रहे हैं?

क्या यह कविता केवल छात्रों के लिए प्रेरणादायक थी या किसी गहरे वैचारिक आग्रह की परिणति थी? डॉ. गंगवार का अतीत अगर देखा जाए तो वे एक समय एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, लेकिन उनकी कविता उस विचारधारा से मेल नहीं खाती। बल्कि उन्होंने जिस प्रकार की भाषा और प्रतीक का इस्तेमाल किया, वह उन्हीं लोगों की धार्मिक परंपराओं पर कटाक्ष करती है जिनके बीच वे पहले खड़े रहे थे। इसलिए एबीवीपी ने भी तुरंत उन्हें निलंबित कर दिया। यह विरोधाभास इस बात का संकेत है कि शिक्षा के क्षेत्र में अब केवल ज्ञान नहीं, विचारधारा भी प्रवेश कर चुकी है।

भारत जैसे देश में, जहां धर्म केवल आस्था का नहीं, बल्कि जीवन पद्धति का हिस्सा है, वहां किसी धार्मिक परंपरा को इस प्रकार नकारात्मक रूप में दिखाना केवल विवाद नहीं, बल्कि सामाजिक विभाजन को गहरा करना है। यह विभाजन दो ध्रुवों में बंटता जा रहा है एक ओर वे लोग हैं जो तर्क, वैज्ञानिक सोच और शिक्षा को सर्वोपरि मानते हैं

कविता की पंक्तियां थीं, "कांवड़ ढोकर कोई डीएम, एसपी नहीं बना है। भांग, धतूरा, गांजा, सुल्फा मद से कोई उद्धार नहीं हुआ है। तुम कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना।" शब्दों की गहराई को देखें तो यह सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि कटाक्ष था। "कांवड़", "गांजा", "धतूरा", "सुल्फा" जैसे शब्दों का संयोजन उस धार्मिक परंपरा पर प्रश्न चि लगाता है जो करोड़ों लोगों के लिए एक श्रद्धा है।

और दूसरी ओर वे हैं जो परंपरा, आस्था और धार्मिकता को अपनी पहचान का मूल मानते हैं। लेकिन क्या यह जरूरी है कि ये दोनों विचारधाराएं एक–दूसरे की विरोधी हों? क्या हम ऐसा समाज नहीं बना सकते, जहां एक बच्चा शिवभक्त भी हो और वैज्ञानिक सोच वाला भी? क्या वह कांवड़ भी उठा सकता है और आईएएस भी बन सकता है? भारत का इतिहास तो यही कहता है कि यहां धर्म और ज्ञान साथ चलते हैं।

इस पूरे विवाद में एक और पहलू जो ध्यान देने लायक है, वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। डॉ. गंगवार ने माफीनामा जारी कर कहा कि उनका उद्देश्य किसी धर्म का अपमान नहीं था। लेकिन भारत का संविधान भी यही कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरंकुश नहीं हो सकती। अनुच्छेद 19(2) के तहत, यह स्वतंत्रता कुछ सीमाओं के भीतर ही स्वीकार्य है, जिनमें सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और दूसरों की भावनाएं शामिल हैं। एक शिक्षक को यह समझना चाहिए कि वह कक्षा में जो कहता है, वह केवल विचार नहीं, बल्कि मूल्य बनकर विद्यार्थियों के मन में बस जाता है। इसीलिए शिक्षकों के शब्दों में विशेष जिम्मेदारी होनी चाहिए। वे अगर कुछ कहना भी चाहते हैं, तो उसमें कटाक्ष नहीं, सहमति और संतुलन होना चाहिए।

राजनीतिक प्रतिक्रिया ने भी इस मामले को और जटिल बना दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉ. गंगवार के समर्थन में बयान दिया और कहा कि एक शिक्षक बच्चों को ज्ञान की बात कर रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर करना असहिष्णुता है। यह बात एक सीमित नजरिए को दर्शाती है। सवाल यह है कि अगर यही कविता किसी अन्य धर्म की धार्मिक यात्रा पर होती, तो क्या यही समर्थन होता? क्या यही लोग तब भी खड़े होते? यह दोहरा मापदंड भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर राजनीतिक एजेंडे को उजागर करता है।

यह विवाद एक आईना है, जिसमें भारत की शिक्षा व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता और राजनीतिक हस्तक्षेप तीनों को साफ देखा जा सकता है। शिक्षक अब केवल पढ़ाने वाले नहीं रह गए, वे अब विचारधारा का माध्यम भी बनते जा रहे हैं।

यह स्थिति खतरनाक है। अगर कक्षा में ज्ञान के स्थान पर तिरस्कार परोसा जाने लगे, तो भविष्य का समाज असंतुलित और बंटा हुआ होगा। यह घटना हमें चेतावनी देती है कि हमें अपने शिक्षकों को केवल विषय विशेषज्ञ नहीं, बल्कि संवेदनशील विचारक बनाना होगा। उन्हें यह सिखाना होगा कि कैसे वे विद्यार्थियों को प्रेरित करें बिना किसी विश्वास या परंपरा को नीचा दिखाए। शिक्षा का काम बच्चों को सोचने की क्षमता देना है, न कि उन्हें किसी खास दिशा में मोड़ना। अगर शिक्षक अपनी बात को कहने के लिए किसी समुदाय की आस्था पर हमला करेगा, तो वह शिक्षक नहीं, प्रचारक कहलाएगा।

अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि "तुम कांवड़ लेने मत जाना" जैसी कविताएं अगर छात्रों को पढ़ाई की ओर ले जाती हैं, तो उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें न व्यंग्य हो, न तिरस्कार। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में संतुलन ही सबसे बड़ा धर्म है। शिक्षक अगर इस संतुलन को नहीं साध सके, तो फिर कौन साधेगा?

इस मामले में केवल शिक्षक नहीं, पूरा समाज कठघरे में है। हमें यह तय करना होगा कि शिक्षा को कैसे एक ऐसी भूमि बनाई जाए जहां सभी विचार, सभी विश्वास, और सभी रास्ते साथ चल सकें। यही भारतीयता है, यही भारत की

कट्टरपंथ के खिलाफ पढ़े-लिखे मुसलमानों की खामोशी के मायने

भारत में धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में लव जेहाद, आतंकवाद, धर्मांतरण और गजवा-ए-हिन्द जैसे मुद्दों ने इस सामाजिक ताने-बाने को गंभीर चुनौती दी है।

संजय सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

विशेषकर हिंदू समाज और बेटियों के माता–पिता के मन में भय गहरा होता जा रहा है। लव जेहाद शब्द सबसे पहले 2009 में केरल और कर्नाटक पुलिस की जांच में सामने आया। बाद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए कानून भी बनाए। 2020 में उत्तर प्रदेश में बना कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति शादी के नाम पर जबरन धर्मांतरण करता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। यूपी के बलरामपुर में ऐसा ही एक मौलाना पकड़ा गया, जो हिन्दू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों के सहारे बरगलाने का सिंडिकेट चला रहा था। इसने हिन्दू लड़कियों के धर्मांतरण के लिये उनकी जाति के अनुसार रेट तक फिक्स कर रखे थे।

धर्मांतरण का मुद्दा ऐतिहासिक रूप से भी विवादास्पद रहा है। 1920 में आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, ताकि जबरन या धोखे से धर्मांतरण करने वालों को फिर से हिंदू धर्म में लाया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह भी

स्पष्ट है कि यह स्वतंत्रता जबरन या धोखे से किए गए परिवर्तन पर लागू नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में रतन लाल केस में कहा था कि धर्म परिवर्तन तभी वैध है जब वह पूरी तरह स्वेच्छा से हो। बात गजवा–ए–हिन्द की कि जाए तो इसकी अवधारणा का जिक्र 13वीं सदी की इस्लामी किताबों में मिलता है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 2003 में एक इंटरव्यू में कहा था, भारत को कमजोर करने के लिए कश्मीर से शुरू करके पूरे भारत में जिहाद फैलाना हमारी रणनीति का हिस्सा है। इसी तरह, हाफिज सईद ने भी कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि हमारा अंतिम लक्ष्य गजवा–ए–हिन्द है।

केरल के प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान मौलाना कनीमैय्यून ने 2020 में एक टीवी डिबेट में कहा था, इस्लाम में किसी भी तरह का जबरन धर्मांतरण हराम है। लेकिन समाज के भीतर कट्टरपंथी सोच इतनी गहरी हो गई है कि लोग खुलकर बोलने से डरते हैं। इसी तरह, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने एक इंटरव्यू में कहा था, हमारे समाज में सुधार की सबसे बड़ी जरूरत है। जब तक हम कट्टरपंथ के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तब तक मुसलमानों की छवि सुधर नहीं सकती। सुप्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मुस्लिम समाज के भीतर सुधार की आवाज उठाने वालों को गद्दार कहकर चुप कराया जाता है। जब तक मुस्लिम समाज खुद सामने आकर कट्टरपंथ को नकारेगा नहीं, तब तक महिलाएं और लड़कियां सबसे ज्यादा पीड़ित रहेंगी।

कई सर्वे और रिपोर्ट बताते हैं कि 2021 में हुए एक सर्वे में लगभग 60 फीसदी हिंदू माता–पिता ने कहा कि वे अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने से डरते हैं। वजह यह कि कहीं उनकी बेटियाँ कथित प्रेमजाल में फँसकर जबरन धर्म परिवर्तन न कर लें। धर्मांतरण के मामलों में भी कई दर्दनाक उदाहरण सामने आए हैं। 2017 में केरल की हदिया केस में जबरन धर्मांतरण और शादी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक

कई सर्वे और रिपोर्ट बताते हैं कि २०२१ में हुए एक सर्वे में लगभग ६० फीसदी हिंदू माता-पिता ने कहा कि वे अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने से डरते हैं। वजह यह कि कहीं उनकी बेटियाँ कथित प्रेमजाल में फँसकर जबरन धर्म परिवर्तन न कर लें। धर्मांतरण के मामलों में भी कई दर्दनाक उदाहरण सामने आए हैं।

पहुँचा। हदिया ने बाद में अदालत में कहा कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला, लेकिन एनआईए की रिपोर्ट में कई संदिग्ध नेटवर्क के लिंक सामने आए। इस तरह की वारदातों पर मुस्लिम समाज के पढ़े–लिखे वर्ग की खामोशी पर दिल्ली के मौलाना वहीदुद्दीन खान ने कहा था, मुसलमानों को चाहिए कि वे साफ–साफ कहें कि वे कट्टरपंथ के साथ नहीं खड़े हैं। अगर आप चुप रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहे हैं।

इतिहास में भी इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। औरंगजेब के काल में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया और हजारों मंदिर तोड़े गए। जबकि अकबर ने दीन–ए–इलाही जैसी नई धार्मिक विचारधारा के जरिए सहिष्णुता का संदेश दिया। यह ऐतिहासिक घटनाएँ आज भी समाज में अविश्वास की जड़ें मजबूत करती हैं। सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी विचारों का प्रचार भी एक बड़ा कारण है। कई बार वीडियो और संदेश वायरल होते हैं, जिनसे समाज में भय फैलता है।

कुछ मामलों में यह सच भी निकलता है, जैसे कि कर्नाटक की एक छात्रा के केस में, जहाँ लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया गया और बाद में उसे विदेश भेजने की साजिश रची गई। इन तमाम घटनाओं और ऐतिहासिक संदर्भों के बीच पढ़े–लिखे मुसलमानों और बुद्धिजीवियों की खामोशी हिंदू समाज में भय और असुरक्षा की भावना को और बढ़ा देती है। खासकर बेटियों के माता–पिता को लगता है कि उनकी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान अब खतरे में है।

भारत में आतंकवाद की घटनाओं ने न सिर्फ देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी गहरा आघात पहुंचाया है। 2001 में संसद पर हुआ हमला भारत के लोकतंत्र के मंदिर को निशाना बनाने की साजिश थी, जबकि 2008 के मुंबई हमले में आतंकियों ने आम नागरिकों को बंधक बनाकर देश की आर्थिक राजधानी को दहला दिया। 2016 के उरी हमले में सेना के 19 जवान शहीद हुए, और 2019 के पुलवामा आत्मघाती हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत ने देश को झकझोर दिया। सबसे हालिया 22 अप्रैल 2025 को जम्मू–कश्मीर के पहलगाम स्थित बीसारन घाटी में हुए आतंकी नरसंहार ने इस खतरनाक मानसिकता की पराकाष्ठा दिखा दी। पहलगाम में आतंकियों ने यात्रियों की धर्म के आधार पर पहचान की और 26 निर्दोषों जिनमें 25 हिंदू और एक ईसाई शामिल था की निर्मम हत्या कर दी, जबकि एक स्थानीय मुस्लिम गाइड ने कई लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवाई। इन घटनाओं के बाद देशभर में आक्रोश की लहर उठी, लेकिन एक बार फिर पढ़ा–लिखा मुसलमान वर्ग और तथाकथित सेक्युलर बुद्धिजीवी चुप रहे। उनकी यह खामोशी समाज में अविश्वास को और गहरा करती है, और यह सवाल उठता है कि जब आतंकवाद इस हद तक इंसानियत का गला घोंट रहा हो, तब क्या चुप रहना भी कहीं न कहीं उस अपराध की मौन स्वीकृति नहीं है?

लब्बोलुआब यह है कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है, लेकिन इस विविधता को बचाने के लिए जरूरी है कि मुस्लिम समाज का पढ़ा–लिखा वर्ग और बुद्धिजीवी खुलकर बोलें। उन्हें यह बताना होगा कि लव जेहाद, आतंकवाद और जबरन धर्मांतरण इस्लाम के खिलाफ हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो समाज में अविश्वास और भय की खाई और गहरी होती जाएगी। यह समय चुप्पी साधने का नहीं है, बल्कि सच के

साथ आये उद्धव-राज ठाकरे की मराठी मानुषों पर सियासी नजर

दोनों भाइयों ने एक साथ आने पर एक सुर में प्रतिक्रिया व्यक्त की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहाकि जो बाल साहब ठाकरे नहीं कर सके, वह आज देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया।

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेला हुआ है। दशकों से सियासत की दुनिया में एक–दूसरे के दुश्मन बने दो भाई एक हो गये हैं। बात राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की हो रही है। दोनों भाइयों ने एक साथ आने पर एक सुर में प्रतिक्रिया व्यक्त की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहाकि जो बाल साहब ठाकरे नहीं कर सके, वह आज देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। उन्होंने हम दोनों भाइयों को साथ खड़ा कर दिया। वहीं, इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने भी राज ठाकरे के सुर में सुर मिलाया। उन्होंने कहा कि हम क्या कहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है यह है कि हम साथ हैं। हम साथ आए हैं और साथ ही रहेंगे। हमें इस्तेमाल करके फेंकने वालों को अब हम फेंकेंगे।

इस मौके पर दोनों ने कई मुद्दो पर अपनी प्रतिक्रिया दीं। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपने हमें बहुत इस्तेमाल कर लिया है। अगर आपके पास बालासाहेब ठाकरे का समर्थन न होता तो आपको महाराष्ट्र में कौन जानता? आप हमें हिंदुत्व सिखाने वाले हैं कौन? उद्धव ने कहा कि जब मुंबई में दंगे हो रहे थे मराठा लोगों ने महाराष्ट्र में सभी हिंदुओं को बचाया था, चाहे वो कोई भी होंगे। अगर आप विरोध के लिए, न्याय पाने के लिए लड़ रहे मराठी लोगों को गुंडा कह रहे हैं तो ठीक है, हम गुंडा हैं। इससे पहले इस मौके पर राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी अच्छी भाषा है। हमें हिंदी अच्छी लगती है। सारी भाषाएं अच्छी हैं। लेकिन हिंदी भाषा को थोपा जाना बर्दाश्त नहीं। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठी लोगों की मजबूत एकता के कारण त्रिभाषा फार्मूले पर फैसला वापस लिया। त्रिभाषा फार्मूला पर फैसला मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश का मुख्य हिस्सा था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने केंद्र सरकार पर कथित रूप से देशभर में हिंदी थोपने को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की आलोचना की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी उसकी हिंदुत्व की परिभाषा पर सवालों के घेरे में खड़ा किया। राज ठाकरे ने लाल कृष्ण आडवाणी का उदाहरण देते हुए कहा, एल के आडवाणी मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं। क्या वह कम हिंदू हो गए?

राज ठाकरे ने आगे कहा कि भाषा का व्यक्ति से क्या लेना–देना? उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे और मेरे पिता श्रीकांत ठाकरे ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की। बालासाहेब ठाकरे ने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई की, अंग्रेजी अखबार में काम किया लेकिन मराठी को लेकर कभी समझौता नहीं किया। दक्षिण भारत के कई राजनीतिक नेता और फिल्मी हस्तियां अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ी, लेकिन उन्हें तमिल और तेलुगु भाषा पर गर्व है। लालकृष्ण आडवाणी ने सेंट पैट्रिक हाईस्कूल में पढ़ाई की, जो एक मिशनरी स्कूल था, लेकिन उनके हिंदुत्व पर शक कर सकते हैं? मनसे प्रमुख ने कहा कि महाराष्ट्र से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लिए जो कर सकते हैं करेंगे। राज ठाकरे ने इस दौरान कहा कि भाषा के बाद यह लोग जाति की राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मराठी लोगों को कभी एक साथ नहीं आने देंगे। राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी बोलने वाले राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। लोग वहां से भागकर गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की तरफ आ रहे हैं।

राज ठाकरे ने आगे कहा कि यह लोग बस वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर हिंदी लागू करने का यह फैसला चुपचाप स्वीकार कर लिया जाता तो आगे यह लोग अगले कदम के रूप में मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर देते। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषी राज्यों पर कई साल तक मराठा शासन रहा। लेकिन क्या वहां पर कभी हमने मराठी लागू करने की कोशिश की? राज ठाकरे ने तंज करते हुए कहा कि मंत्रियों की हिंदी सुनोगे तो गिर पड़ोगे।

कुल मिलाकर दोनों नेता हिन्दी और महाराष्ट्र में काम धंधा करने वाले यूपी–बिहार के हिन्दी बोलने वाले लोगों का विरोध करके मराठी मानुष के वोट को साधने की कोशिश करते नजर आये।

देहरादून में दिखाई देगी 186 साल पुराने इतिहास की झलक, राष्ट्रपति तपोवन में सुकून के पल बिता सकेंगे पर्यटक

देहरादून में अब आप 186 साल पुराने ऐतिहासिक धरोहर की झलक देख सकेंगे। हाल ही में खुले राष्ट्रपति तपोवन में आपको शहर की हलचल से दूर, जंगल जैसी शांति और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव मिलेगा। यह स्थान उन लोगों के लिए आदर्श है, जो प्रकृति की गोद में सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने जन्मदिन पर राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन किया था, जो युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय हो गया। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। साथ ही, राष्ट्रपति निकेतन भी अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, जहां एक ऐतिहासिक हवेली, हरे–भरे उद्यान और खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं। इसकी ऐतिहासिक विरासत, शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता लोगों को खासा आकर्षित कर रही है। शहर में एक के बाद एक नए पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं, जहां पर्यटक भीड़भाड़ से दूर शांति का अनुभव ले सकते हैं।

1838 से जुड़ा है राष्ट्रपति निकेतन का इतिहास

करीब 186 साल पहले, यानी 1838 में, राष्ट्रपति निकेतन की नींव रखी गई थी। इसे पहले गवर्नर जनरल के बॉडीगार्ड्स के घोड़ों के लिए समर कैंप के रूप में बनाया गया था। वर्ष 1920 में यहां एक सुंदर बंगला बनाया गया, जिसमें यूनिट के कमांडेंट निवास करते थे। स्वतंत्रता के बाद यही बंगला राष्ट्रपति का रिट्रीट हाउस बन गया, जहां कई राष्ट्रपति गर्मियों में आकर ठहरते थे। इसके साथ ही राष्ट्रपति के घोड़ों की ट्रेनिंग भी यहीं होती थी।

जल्द खुलेगा राष्ट्रपति उद्यान भी

अगले साल देहरादून में 132 एकड़ में फैला नया राष्ट्रपति उद्यान भी खोला जाएगा। यह सिर्फ घूमने की जगह नहीं होगी, बल्कि इसे एक जीवंत कक्षा (लिविंग क्लासरूम) की तरह तैयार किया जा रहा है, जहां लोग प्रकृति से जुड़कर नई–नई बातें सीख सकेंगे।

प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है राष्ट्रपति तपोवन

राष्ट्रपति निकेतन के बगल में फैले 19 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रपति तपोवन स्थित है। यहां घने पेड़ों की छांव, लकड़ी के पुल, बर्ड वॉचिंग टॉवर और मेडिटेशन के शांत कोने मिलते हैं, जो किसी जंगल जैसे अनुभव कराते हैं। यहां 52 प्रकार की तितलियां, 41 पक्षियों की प्रजातियां, 117 तरह के पौधे और 7 जंगली स्तनधारी जीव पाए जाते हैं, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए इसे एक आदर्श स्थान बनाते हैं।

1976 में बना आधिकारिक राष्ट्रपति निवास

1976 में इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति निवास घोषित किया गया। तब से लेकर अब तक इसकी विरासत को संजोने का कार्य लगातार जारी है। वर्तमान में इसका रिट्रीट हाउस नवीनीकरण (रेनोवेशन) के दौर से गुजर रहा है। सिटी पीडब्लूडी की टीम इस पर कार्य कर रही है ताकि इसकी पुरानी शान और स्थापत्य शैली को बरकरार रखा जा सके। काम पूरा होने के बाद इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी।

बिहार में वोटर लिस्ट जांच पर सबके अपने दावे और विचार

विपक्षी दल इस प्रक्रिया को लोकतंत्र पर हमला और गरीब, दलित, पिछड़े, और अल्पसंख्यक समुदायों के मताधिकार को छीनने की साजिश करार दे रहे हैं।

संजय सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

बिहार में कुछ माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिये उठाये गये कदम ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया को लोकतंत्र पर हमला और गरीब, दलित, पिछड़े, और अल्पसंख्यक समुदायों के मताधिकार को छीनने की साजिश करार दे रहे हैं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग इसे नियमित और संवैधानिक प्रक्रिया बताकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। यह विवाद अब दिल्ली के निर्वाचन सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, और बिहार की सियासत में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। दस जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर सकता है।

विपक्षी दलों, विशेष रूप से इंडिया गठबंधन के घटक दलों जैसे कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), समाजवादी पार्टी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस पुनरीक्षण प्रक्रिया को वोटबंदी करार दिया है। 2 जुलाई 2025 को 11 विपक्षी दलों का 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में निर्वाचन सदन पहुंचा और चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, राजद के मनोज झा, और सीपीआई (एमएल) के दीपांकर भट्टाचार्य जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। इसी क्रम में ओवैसी ने भी अलग से चुनाव आयोग पहुंच कर अपना पक्ष रखा। विपक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में शुरू की गई है और यह गरीब, ग्रामीण, और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को मतदाता सूची से हटाने की साजिश है।

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिहार में लगभग 7.75 करोड़ मतदाता हैं। इतनी बड़ी संख्या की जांच कुछ महीनों में करना असंभव है। यह

विपक्षी नेताओं का तर्क है कि सत्यापन के लिए मांगे गए ११ दस्तावेज, जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, और माता-पिता की नागरिकता प्रमाण, अधिकांश गरीब और ग्रामीण लोगों के पास उपलब्ध नहीं हैं। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार के ८ करोड़ से अधिक मतदाताओं में से ६० फीसदी को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, जो विशेष रूप से दलित, पिछड़े, और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चुनौतीपूर्ण है।

प्रक्रिया उन लोगों को निशाना बनाएगी जिनके पास जन्म प्रमाणपत्र या माता–पिता की नागरिकता जैसे दस्तावेज नहीं हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे और तीखे शब्दों में लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने सवाल उठाया, 2003 में पूरे देश में पुनरीक्षण हुआ था, लेकिन अब सिर्फ बिहार में क्यों? यह प्रक्रिया मानसून के दौरान, जब बाढ़ आम है, शुरू की गई है। क्या यह गरीब और वंचित वोटरों को बाहर करने की साजिश नहीं है?

विपक्षी नेताओं का तर्क है कि सत्यापन के लिए मांगे गए 11 दस्तावेज, जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, और माता–पिता की नागरिकता प्रमाण, अधिकांश गरीब और ग्रामीण लोगों के पास उपलब्ध नहीं हैं। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार के 8 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से 60 फीसदी को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, जो विशेष रूप से दलित, पिछड़े, और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चुनौतीपूर्ण है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक बताते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है और इसे दोहराने का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे बीजेपी–आरएसएस की साजिश बताया, जिसका मकसद दलितों और वंचितों के वोटिंग अधिकार छीनना है। योगेंद्र यादव ने अनुमान लगाया कि इस प्रक्रिया से 4.76 करोड़ मतदाताओं का नाम हट सकता है, जिसे उन्होंने वोट उड़ाने का खेल करार दिया।

उधर बीजेपी और एनडीए ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए जरूरी है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा, जिनके राज में बूथ कैप्चरिंग और हिंसा आम थी, उन्हें अब निष्पक्षता से परेशानी हो रही है। हालांकि, एनडीए के कुछ सहयोगी, जैसे जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), ने दबी जुबान में इस प्रक्रिया की समय सीमा पर चिंता जताई है। बहरहाल, कुल मिलाकर लगता है कि बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसकी समय सीमा और दस्तावेजों की मांग ने इसे विवादास्पद बना दिया है। विपक्ष इसे गरीब और वंचित समुदायों के खिलाफ एक साजिश के रूप में देख रहा है, जबकि चुनाव आयोग इसे लोकतंत्र को मजबूत करने का कदम बता रहा है। यह विवाद बिहार की सियासत को और गर्माएगा, और इसका असर 2025 के विधानसभा चुनावों पर पड़ना तय है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में निर्णायक हो सकता है, लेकिन तब तक यह मुद्दा बिहार की जनता और नेताओं के बीच बहस का केंद्र बना रहेगा। विपक्ष की आपत्तियों ने अब कानूनी रूप ले लिया है। सपा सांसद कपिल सिब्बल, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, राजद के मनोज झा, और कई गैर–सरकारी संगठनों ने इस प्रक्रिया को रद्द करने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की, यह तर्क देते हुए कि इतने कम समय में यह प्रक्रिया संभव नहीं है और यह संविधान का उल्लंघन करती है। इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई 2025 को होनी है।

चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक और नियमित है, जो पिछले 75 वर्षों से समय–समय पर की जाती रही है। आयोग का कहना है कि इसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, और म्यांमार से आए लोगों, को मतदाता सूची से हटाना और केवल भारतीय नागरिकों को वोटिंग का अधिकार सुनिश्चित करना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 4 जुलाई को स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया तय समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएगी। चुनाव कर्मियों और राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 2003 की मतदाता सूची को आधार मानकर 4.96 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही, एक गलतफहमी को दूर करते हुए आयोग ने कहा कि एक अखबार के विज्ञापन में केवल फॉर्म भरने की बात भ्रामक थी। मसौदा सूची में उन मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जिनके गणना फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। आयोग ने यह भी बताया कि यह प्रक्रिया बिहार के अलावा असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल में भी लागू होगी। इसका मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना, मृतकों के नाम हटाना, और 18 वर्ष से अधिक उम्र के

मोहर्रम के दौरान ईरानी नेता खामनेई के कसीदे क्यों

हाल ही में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव, लखनऊ सहित देश के कई राज्यों में मोहर्रम के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बैनर-पोस्टर लगाए गए, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

संजय सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों और जम्मू–कश्मीर के श्रीनगर में हाल ही में दो घटनाएं एक जैसी घटीं, जिन्होंने देशभर में एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल, भारत में मोहर्रम के दौरान शिया समुदाय द्वारा इमाम हुसैन की शहादत को याद करने के लिए जुलूस, ताजिया और मातम का आयोजन किया जाता है। इस पवित्र महीने में मुसलमानों की धार्मिक भावनाएँ प्रबल होती हैं, और विशेष रूप से शिया समुदाय अपने धार्मिक गुरुओं को सम्मान देता है। ऐसे मौके पर अक्सर राजनीति को धर्म से दूर रखा जाता है, लेकिन हाल ही में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव, लखनऊ सहित देश के कई राज्यों में मोहर्रम के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बैनर–पोस्टर लगाए गए, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सवाल पूछा जा रहा है कि जब इजरायल और ईरान के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं और भारत दोनों देश के नेताओं को समझा–बूझा रहा है तब समाज का एक वर्ग किसी एक देश की सरकार के पक्ष में क्यों खड़ा दिखाई देता है। वह भी ऐसे मौके पर जब शिया मुलसमान इमाम हुसैन की शहादत को याद करके मातम बना रहे है। यह तर्क दिया जा सकता है कि खामेनेई एक धार्मिक शख्सियत हैं, लेकिन इसके साथ–साथ सच्चाई यह भी है के वह इस समय सियासी रूप में नजर आ रहे हैं।

बहराल, उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों के स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने इन पोस्टरों को हटाने का आदेश दिया, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर विदेशी नेताओं की तस्वीरें लगाना नियमों के खिलाफ माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि यह भारत की संप्रभुता और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा हो सकता है, खासकर जब ईरान–इजरायल संघर्ष की पृष्ठभूमि में इसे राजनीतिक समर्थन के रूप में देखा जाता है। उन्नाव में पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए पोस्टर हटवाए, जिस पर शिया संगठनों ने नाराजगी जताई। मौलाना यासूब अब्बास जैसे धर्मगुरुओं ने इसे धार्मिक भावनाओं पर हमला बताया, जबकि प्रशासन का कहना था कि यह कदम सामुदायिक तनाव को रोकने के लिए जरूरी था।

गौरतलब हो, धर्म के नाम कुछ शिया मुसलमान जो कर रहे हैं उसके चलते भारत–इजरायल के पुराने संबंधों भी प्रभावित हो सकते हैं। कुछ लोग इसे वैचारिक प्रदर्शन मानते हैं, जो इमाम हुसैन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष को दर्शाता है। फिर भी, भारत जैसे बहु–सांस्कृतिक देश में ऐसी गतिविधियां सावधानी बरतने की मांग करती हैं, ताकि सामाजिक एकता बनी रहे। लखनऊ में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का पोस्टर लगाए जाने और श्रीनगर में मुहर्रम के दौरान आतंकी संगठन हिज़्बुल्लाह के झंडे लहराए जाने की घटनाएं न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दायरे में भी चर्चा का विषय बन गई हैं। इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या धार्मिक आस्था की आड़ में भारत

जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में विदेशी एजेंडा पनप रहा है? लखनऊ के अवध पॉइंट स्थित शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास के आवास,शिया डिग्री कालेज, विक्टोरिया स्ट्रीट आदि कुछ स्थानों पर जब अयातुल्ला खामेनेई के बड़े–बड़े पोस्टर लगाये गये, तब कई लोगों ने इसे सामान्य धार्मिक परंपरा माना। मौलाना यासूब ने सफाई दी कि हर साल की तरह इस बार भी हैदरी टास्क फोर्स की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। बहरहाल, शिया धर्मगुरूओं को यही लगता है कि खामेनेई शिया समुदाय के लिए एक धार्मिक गुरु हैं, इसलिए इसमें कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। लेकिन इस बार मामला इसलिए खास बन गया क्योंकि यह पोस्टर ऐसे समय लगाया गया, जब ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन तक भयंकर संघर्ष चला। ऐसे में जब भारत में किसी ऐसे देश के सर्वोच्च नेता की सार्वजनिक तस्वीरें सामने आती हैं, जो खुद को इजरायल का शत्रु घोषित करता है, तो विवाद होना लाजिमी था। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। कई लोगों ने पूछा कि जब भारत की सरकार किसी भी वैश्विक संघर्ष में निष्पक्ष भूमिका अपनाने की नीति पर चल रही है, तब भारत की सड़कों पर विदेशी नेताओं के प्रचार की आवश्यकता क्या है?क्या यह धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है या भारत में विदेशी राजनैतिक विचारधाराओं के लिए जमीन तैयार करने की एक कोशिश? यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि क्या भारत की धार्मिक स्वतंत्रता का दायरा इतना बड़ा है कि उसके भीतर दूसरे देशों की राजनीति को भी छिपने की जगह मिल जाए? क्या धर्म के नाम पर कोई भी समूह किसी विदेशी नेता के लिए समर्थन जुटा सकता है, भले ही उसका भारत से कोई लेना–देना न हो?

इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं। प्रशासन ने उन इलाकों में निगरानी बढ़ा दी जहां शिया आबादी अधिक है। अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को

धर्म के नाम कुछ शिया मुसलमान जो कर रहे हैं उसके चलते भारत-इजरायल के पुराने संबंधों भी प्रभावित हो सकते हैं। कुछ लोग इसे वैचारिक प्रदर्शन मानते हैं, जो इमाम हुसैन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष को दर्शाता है। फिर भी, भारत जैसे बहु-सांस्कृतिक देश में ऐसी गतिविधियां सावधानी बरतने की मांग करती हैं।

लेकर अंदरखाने गंभीरता देखी गई। इससे पहले भी जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, तब मौलाना यासूब अब्बास के नेतृत्व में लखनऊ में प्रदर्शन हुए थे। उस समय इजरायल और अमेरिका के नेताओं के पोस्टर जलाए गए थे और भारत सरकार से ईरान के समर्थन की मांग की गई थी। इस पूरे मामले को तब और तूल मिला जब श्रीनगर की सड़कों पर मुहर्रम के दौरान हिज़बुल्लाह और फिलिस्तीन के झंडे दिखाई दिए। इन झंडों को लेकर न केवल मीडिया में बल्कि प्रशासनिक हलकों में भी चिंता बढ़ गई। यह पहला मौका नहीं है जब श्रीनगर के शिया मुसलमानों ने इस प्रकार की राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ की हों, लेकिन इस बार यह खुलेआम और संगठित रूप से हुआ। हिज़्बुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह और अयातुल्ला खामेनेई के पोस्टर लेकर जुलूस में नारे लगाए गए।हिज़्बुल्लाह एक लेबनानी शिया आतंकी संगठन है, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और खाड़ी के कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। 1983 में बेरूत में अमेरिकी मरीन बैरक पर हमला, 1985 में एक विमान का अपहरण और 1994 में अर्जेंटीना में यहूदी केंद्र पर हमला कृ ये सभी हमले इसी संगठन के नाम हैं।

हिज़्बुल्लाह ईरान समर्थित संगठन है और इसका मकसद इजरायल को मिटाना बताया गया है। भारत से इसका कोई सीधा नाता नहीं है, फिर भी श्रीनगर के कुछ शिया समूह इसे अपना प्रतिनिधि मानते हैं। इस समर्थन का आधार धार्मिक है। शिया मुसलमानों की मान्यता है कि मुहर्रम में इमाम हुसैन ने यजीद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अब इजरायल को आधुनिक यजीद बताया जा रहा है। हिज़्बुल्लाह को श्हुसैनी फौजश की तरह पेश किया जा रहा है, जो इजरायल से लड़ रहा है। इस विचारधारा के मुताबिक हसन नसरल्लाह जैसे नेता आज के दौर में इमाम हुसैन की तरह हैं, जो "जालिम ताकतों" से लड़ रहे हैं। यही कारण है कि इनका समर्थन सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर भी हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस प्रकार की भावनाएं भारत की राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा बन सकती हैं? धार्मिक आयोजन अगर वैश्विक राजनीतिक संघर्षों का मंच बनने लगें तो भारत की गंगा–जमुनी तहजीब को गंभीर चोट पहुँच सकती है। इससे पहले भी श्रीनगर में हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लग चुके हैं। ऐसे माहौल में जब भारत के युवा वैश्विक इंटरनेट पर धार्मिक कट्टरता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तब इन जुलूसों के माध्यम से उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से कट्टरता के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सरकार और खुफिया एजेंसियों को अब यह सोचना होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्र हित के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। धार्मिक आयोजन और जुलूसों पर नजर रखना अब केवल सांप्रदायिक तनाव से बचने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी हो गया है। अगर कोई धार्मिक समूह विदेशी आतंकी संगठन के झंडे लहराता है, तो यह केवल धार्मिक भावना नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता के लिए सीधा खतरा है। सरकार को चाहिए कि वह स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी करे कि धार्मिक आयोजनों में विदेशी नेताओं, संगठनों या झंडों का प्रदर्शन प्रतिबंधित हो। धार्मिक नेताओं को भी यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वे धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक रंग न दें।

धर्म और राजनीति का मिश्रण एक ऐसा विस्फोटक मेल है जो समाज की जड़ों को हिला सकता है। यह भी आवश्यक है कि मुस्लिम समुदाय के भीतर से ही इस प्रकार की गतिविधियों का विरोध हो। भारत में अधिकांश मुसलमान देशभक्त हैं और भारत के संविधान में विश्वास रखते

बिहार चुनाव 2025

ईमान, इस्लाम और इंतकाम के त्रिकोण में उलझा मुस्लिम वोट बैंक

यह न सिर्फ चुनावी रणनीतियों को जटिल बना रहा है, बल्कि मुस्लिम मतदाताओं को भी गहरे अंतर्द्वंद्व में डाल रहा है। राज्य में लगभग १.८ करोड़ मुस्लिम मतदाता हैं, जो कुल मतदाताओं का करीब १७.८: हिस्सा हैं।

संजय सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से एक निर्णायक शक्ति रहा है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में यह वोट बैंक पहली बार तीन गहरे और परस्पर विरोधी विमर्शों के बीच फंसा हुआ है ईमान, इस्लाम, और इंतकाम। यह न सिर्फ चुनावी रणनीतियों को जटिल बना रहा है, बल्कि मुस्लिम मतदाताओं को भी गहरे अंतर्द्वंद्व में डाल रहा है। राज्य में लगभग 1.8 करोड़ मुस्लिम मतदाता हैं, जो कुल मतदाताओं का करीब 17.8: हिस्सा हैं। सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी, सारण और पटना जिलों की करीब 47 विधानसभा सीटों पर ये वोट निर्णायक हैं। ऐसे में हर दल इस वर्ग को अपने पाले में लाने की होड़ में है लेकिन इस बार वह होड़ विचारधारात्मक स्तर तक जा पहुंची है।

राजद नेता तेजस्वी यादव मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए दो प्रमुख आयामों पर काम कर रहे हैं पहला, धार्मिक पहचान की रक्षा और दूसरा, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश को संगठित करना। वक्फ अधिनियम में बदलाव, एनआरसी, एनपीआर और वोटर लिस्ट से मुस्लिम नामों को हटाने जैसे मुद्दों को उन्होंने चुनावी मंचों पर बार–बार उठाया है। इससे वे मुस्लिम मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन ही उनकी धार्मिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। हालांकि, 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के जीते पांच में से चार विधायकों को तोड़कर राजद में शामिल कर लेना तेजस्वी के "मुस्लिम हितैषी" दावे को कमजोर भी करता है। असदुद्दीन ओवैसी इसे "सियासी धोखा" बताते हैं। तेजस्वी यादव के लिए सीमांचल की सीटें अभी भी एक परीक्षा की घड़ी हैं, जहां मुस्लिम मतदाता न केवल पहचान के आधार पर, बल्कि अब प्रतिनिधित्व और आत्मसम्मान के आधार पर भी सोचने लगे हैं।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस बार राजद से दूरी बनाते हुए

बिहार में एक तीसरे मोर्चे की भूमिका में आना चाहते हैं। उनका तर्क है कि जब 2020 में सीमांचल की जनता ने उन्हें चुना, तब महागठबंधन ने उनके विधायकों को तोड़कर राजनीतिक विश्वासघात किया। इसी "इंतकाम" की भावना को वे इस बार चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन जब कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। एआईएमआईएम अब सीमांचल से बाहर दरभंगा, पटना, भागलपुर और किशनगंज जैसे इलाकों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इससे महागठबंधन को नुकसान तय है, क्योंकि मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा, जो अंततः बीजेपी–एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इस चुनाव में एक अलग तरह का नैरेटिव लेकर आए हैं। वे मुस्लिम समुदाय की गरीबी और पिछड़ेपन को उसकी 'राजनीतिक चूक' का नतीजा बताते हैं। उनका साफ कहना है कि "मुसलमानों ने दशकों तक सिर्फ डर के आधार पर वोट डाले हैं, खासकर राजद को, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ प्रतिनिधित्व की बजाय प्रतीकात्मकता मिली है। प्रशांत किशोर का आह्वान है कि मुस्लिम

सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी, सारण और पटना जिलों की करीब ४७ विधानसभा सीटों पर ये वोट निर्णायक हैं। हर दल इस वर्ग को अपने पाले में लाने की होड़ में है लेकिन इस बार वह होड़ विचार धारात्मक स्तर तक जा पहुंची है।

मतदाता अब 'ईमान' यानी नैतिक दृष्टिकोण से वोट करें और ऐसे प्रतिनिधि चुनें जो सिर्फ धार्मिक भावनाओं की राजनीति न करें बल्कि समाज के आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान की बात करें। उनकी योजना है कि वे 75 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारें और इन्हें नए नेतृत्व के रूप में पेश करें। हालांकि, उनकी पार्टी की संगठनात्मक उपस्थिति अभी कमजोर है और उन्हें जमीन पर पकड़ बनाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू इस बार एनडीए के भीतर एक सॉफ्ट सेकुलर छवि पेश करने की कोशिश में लगे हैं। वे मुस्लिम मतदाताओं को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू ने पिछले दो दशकों में अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जैसे छात्रवृत्ति, मदरसा आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक आवास योजना आदि। इसके अलावा, बीजेपी और जेडीयू की रणनीति पसमांदा मुसलमानों यानी अजलाफ और अरजाल वर्गों को साधने की है। बीजेपी ने 'पसमांदा मुस्लिम सम्मेलन' कर संकेत दिया है कि वह अब अल्पसंख्यक समाज के उस वर्ग को साथ जोड़ना चाहती है, जो अभी तक मुख्यधारा से बाहर रहा है। लेकिन वक्फ अधिनियम में बदलाव और एनआरसी पर नीतीश कुमार की चुप्पी मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग को असहज कर रही है। खासकर वह तबका जो खुद को सामाजिक न्याय के दायरे में देखता है, वह इस चुप्पी को श्राजनीतिक सहमतिश मानता है।

इस बार सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुस्लिम वोट बैंक बिखरेगा या किसी एक राजनीतिक ध्रुव के इर्द–गिर्द संगठित हो जाएगा? 2020 में महागठबंधन को 76ः मुस्लिम वोट मिले थे, एआईएमआईएम को 11ः और एनडीए को 10ः से भी कम। लेकिन 2025 में एआईएमआईएम के विस्तार, प्रशांत किशोर के हस्तक्षेप और एनडीए की रणनीति के चलते यह समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। यदि तेजस्वी, ओवैसी और प्रशांत किशोर आपस में कोई सामंजस्य नहीं बनाते, तो मुस्लिम वोट कम से कम तीन हिस्सों में बंट सकता है। इसका सीधा फायदा बीजेपी और जेडीयू को मिल सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां बहुमत थोड़ा–बहुत फर्क कर सकता है दूसरी ओर, यदि एआईएमआईएम सीमांचल में अपनी सीटें बरकरार रखती है, प्रशांत किशोर पसमांदा मुस्लिमों को कुछ हद तक प्रभावित करते हैं और राजद पारंपरिक मुस्लिम–यादव समीकरण को बचा पाती है, तो मुस्लिम वोटरों की भूमिका सत्ता के संतुलन को पूरी तरह से बदल सकती है। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक अब केवल धार्मिक पहचान का मामला नहीं रहा। यह अब प्रतिनिधित्व, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और राजनीतिक आत्मसम्मान का मुद्दा बन चुका है। ईमान (सही प्रतिनिधित्व), इस्लाम (धार्मिक सुरक्षा) और इंतकाम (सियासी बदला) इन तीनों आयामों के बीच मुस्लिम मतदाता अब विचार कर रहा है। अगले कुछ महीनों में यह तय होगा कि मुस्लिम वोटर पारंपरिक ध्रुवीकरण से ऊपर उठकर नए विकल्पों की ओर जाते हैं या फिर एक बार फिर पुराने समीकरणों को

राजस्थान में बेटी के जन्म पर मिलेगी 1.50 लाख की सहायता,

'मुख्यमंत्री राजश्री योजना' अब बनी 'लाडो प्रोत्साहन योजना'

राजस्थान सरकार ने बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार लाने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 1 जून 2016 को "मुख्यमंत्री राजश्री योजना" की शुरुआत की थी। अब इस योजना का नाम बदलकर 'लाडो प्रोत्साहन योजना' रख दिया गया है।

जयपुरः बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और शिक्षा में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई "राजश्री योजना" को अब 'लाडो प्रोत्साहन योजना' में शामिल कर दिया गया है। इस योजना के तहत अब गरीब परिवार में जन्मी प्रत्येक बालिका को 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पहले यह राशि 1 लाख रुपये थी, जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 मार्च 2025 को बजट सत्र के दौरान बढ़ाने की घोषणा की थी। यह संशोधित योजना 1 अगस्त 2024 से पूरे राजस्थान में लागू हो गई है। सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सात किश्तों में प्रदान की जाएगी। पहली छह किश्तें माता–पिता के खाते में और अंतिम किश्त बालिका के खाते में तब मिलेगी जब वह स्नातक की पढ़ाई पूरी कर 21 वर्ष की उम्र पूरी कर लेगी।

इस योजना का संचालन महिला अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक तीन महीने में कलेक्टर स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी। योजना का लाभ उन सभी बालिकाओं को मिलेगा जिनका जन्म 1 जून 2016 या उसके बाद हुआ है।

सात किश्तों में मिलने वाली राशि

- जन्म के समयः **2,500**
- 1 वर्ष की उम्र व टीकाकरण पूरा होने परः 2,500
- प्रथम कक्षा में प्रवेश परः 4,000
- छठी कक्षा में प्रवेश परः 5,000
- दसवीं कक्षा में प्रवेश परः 11,000
- बारहवीं कक्षा में प्रवेश परः 25,000
- स्नातक उत्तीर्ण एवं 21 वर्ष की उम्र पूरी होने परः 1,00,000

योजना के उद्देश्य

- बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना।
- उनके स्वास्थ्य और सामाजिक स्तर को बेहतर बनाना।
- बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना।
- बाल विवाह और लिंग भेद जैसी कुप्रथाओं को रोकना।

पात्रता शर्तें:

- बालिका राजस्थान की निवासी होनी चाहिए।
- जन्म 1 जून 2016 या उसके बाद हुआ हो।
- जन्म **JSY** पंजीकृत सरकारी या निजी अस्पताल में हुआ हो।
- योजना का लाभ अधिकतम दो बेटियों तक सीमित रहेगा।
- माता–पिता के पास आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड होना जरूरी है।

आवेदन प्रक्रिया

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनी गर्भवती महिलाओं की जानकारी जुटाकर नजदीकी अस्पताल को भेजेंगी।
- विवरण RCH रजिस्टर में दर्ज कर PCTS पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री की जाएगी।
- जिनके पास भामाशाह कार्ड नहीं है, उन्हें ई–मित्र केंद्र पर कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- दस्तावेजों की जांच के बाद किश्तों में सहायता राशि दी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज:

- माता–पिता का आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड
- बालिका का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र
- स्कूल प्रवेश प्रमाण पत्र
- 12वीं की मार्कशीट (यदि लागू हो)
- मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो

मेरा पन्ना

पहली मोहब्बत

कवयित्री प्रज्ञा श्रीवास्तव प्रज्ञाञ्जलि

तुम ही तो मेरी
पहली मोहब्बत थी
याद है ना
जब दिया था ये गुलाब मैंने
अपनी गुलजार को
और शरमा कर तुमने
चूम लिया था उसे
अपने होठों से
और छुपा लिया था
फिलासफी की किताब में
मेरे और तुम्हारे
पाक प्रेम का
वक्त की हवाओं ने
रूख मोड़ दिया
तुम्हारी शादी का कार्ड मिलना
और मेरा विदेश जाना
हमारी आखिरी मुलाकात पर
छोड़ गई थी तुम
वो किताब मेरे पास
जैसे मेरे प्रेम को
लौटा रही हो
आज तुम हास्पिटल के बेड पर
अंतिम सांसे गिन रही हो
और मैं एक लाचार डाक्टर
बेबस खड़ा हूँ
किसको पता था बीस साल बाद
दो प्रेमी युगल
इस तरह मिलेंगे
मेरी सांसे चल रही हैं
और तुम विदा हो रही हो।

आर.एन.आई. नं.- RAJHIN/2019/77486

प्रकाशन की तिथि- प्रत्येक माह की 7 तारीख
प्रेषण दिनांक- प्रत्येक माह की 10 तारीख

विभिन्न विषयों पर आधारित हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

"विशिखा

पत्रिका पाने के लिए सम्पर्क करें

सदस्यता शुल्क	मूल्य प्रति कापी मात्र 25/- रुपये
	एक वर्ष के लिये मात्र 275/- रुपये
	दो वर्ष के लिये मात्र 550/- रुपये

Paytm Accepted Here

Paytm 9587455444

BANK DETAILS-
A/C No. - 6345002100000139
IFSC Code- PUNB0634500
A/C Off- VISHIKHA MEDIA
Bank - Punjab National Bank
Branch - NRI Circle, JAIPUR

विशिखा में विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें

पृष्ठ श्रेणी	कलर	अमांउट
बैक फुल पेज	फोरकलर	₹ 50,000/-
फ्रंट व बैक इनर फुल पेज	फोरकलर	₹ 30,000/-
अन्य फुल पेज	फोरकलर	₹ 20,000/-

विशिखा तीन निशाने पर...

मुख्यालय : विशिखा मीडिया 191/56, सेक्टर-19, प्रताप नगर, सांगानेर
जयपुर-302033 (राज.)
Contactus:+911413562171, 9587455444
E-mail:vishikhamedia@gmail.com | **Website:**www.vishikhamedia.in
vishikhamedia/ _vishikhamedia/ vishikhamedia